RNI-MPHIN/2018/75526

वर्ष-08 |अंक-262| पृष्ठ 08| मूल्य 02/-

दैनिक

कालप्रिया

सच वही जो दिखे...

भोपाल, शुक्रवार

26

जून 2026

Email.kalpriyanews72@gmail.com

ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष-12, विक्रम संवत् 2083

केतन की हत्या के पहले सिया-चेतन कैफे में मिले थे

पुणे। पुणे केतन मर्डर केस में नया वीडियो सामने आया है। केतन की हत्या के एक दिन पहले 17 जून को आरोपी सिया और प्रेमी चेतन चौधरी एक कैफे में मिले थे। पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया कि यहीं लोहगढ़ किले पर केतन को खाई में धक्का देने का प्लान बनाया था। दोनों ने वह पॉइंट भी ढूंढ लिया, जहां से केतन को धक्का देना था। यदि केतन इससे भी बच जाता तो 20 जून के बाद सड़क हादसे में मारने का बैकअप प्लान तैयार था। दरअसल, 31 मई को सिया और मंगेतर केतन लोहगढ़ किले गए थे। वहां केतन एक खतरनाक जगह बैठा था। तभी सिया को उसे मारने का आइडिया आया। केतन मर्डर केस में उसकी मंगेतर सिया और सिया के लवर चेतन को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है।

यहीं मर्डर का प्लान बनाया; सिया बोली- शादी से इनकार किया था, केतन नहीं माना

पासपोर्ट यात्रा दस्तावेज, नागरिकता का प्रमाण नहीं

कांग्रेस ने पूछा- फिर सबूत क्या है; 8 सवाल-जवाब से पूरे मामले को समझें

नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं, ये सिर्फ एक यात्रा दस्तावेज है। 14वीं पासपोर्ट सेवा दिवस सरकार ने कहा कि पासपोर्ट केवल अंतरराष्ट्रीय यात्रा की सुविधा के लिए जारी किया जाता है। इससे पहले एसआईआर से जुड़ी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि आधार कार्ड पहचान का दस्तावेज है, नागरिकता का नहीं। सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत और वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि पासपोर्ट एक यात्रा दस्तावेज है, नागरिकता का दस्तावेज नहीं। तो फिर कौन सा दस्तावेज नागरिकता का सबूत है। वहीं, गीतकार और स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर ने पूछा कि जब पासपोर्ट को नागरिकता का 100 प्रतिशत अकेला और अंतिम सबूत नहीं माना जाता, तो ऐसा कानून क्यों लाया जा रहा है।

पासपोर्ट क्यो होता है? इसका क्या इस्तेमाल है?

पासपोर्ट केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया एक अंतरराष्ट्रीय पहचान पत्र है, जिसका मुख्य इस्तेमाल भारत से बाहर किसी भी देश में यात्रा करने के लिए होता है। विदेश जाने के लिए जरूरी वीजा इसी पर लगता है.

क्या है विदेश मंत्रालय का पूरा बयान?

विदेश मंत्रालय ने 24 जून को 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर एक ब्रीफिंग के दौरान स्पष्ट किया कि भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये मुख्य रूप से एक यात्रा दस्तावेज है। इसका प्राथमिक मकसद नागरिकों को अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने की अनुमति देना और विदेशों में उनकी पहचान व राष्ट्रीयता को स्थापित करना है। हालांकि यह विदेश में आपकी पहचान बताता है, लेकिन यह अपने आप में नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं है। इस प्रावधान के तहत केंद्र सरकार अगर जरूरी समझे तो सार्वजनिक हित में किसी गैर-नागरिक को भी पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी कर सकती है। इसी कानूनी स्थिति के कारण एक पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का पूर्ण या अचूक प्रमाण नहीं माना जा सकता। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कानूनी रूप से भारतीय नागरिकता का निर्धारण नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत होता है.

विदेश मंत्रालय के बयान पर उठे सवाल

"ऐसा लगता है कि आज भारतीय नागरिकता का एकमात्र प्रमाण हिंदू और भाजपा का वोटर होना है। इसके अलावा और कुछ काम नहीं आएगा।"
— महुआ मोइत्रा, तृणमूल सांसद

"अगर अधिकारी इस बात से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे कि पासपोर्ट धारक एक भारतीय नागरिक है, तो पासपोर्ट कैसे जारी किए जा सकते हैं?"
— जावेद अख्तर, गीतकार

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रालय से हितग्राहियों को किया वर्चुअली संबोधित

बुजुर्गों और असहाय लोगों का आदर करना हमारा धर्म:मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि घर में बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद होना, तपती धूप में ठंडी छांव के समान होता है। हमारी संस्कृति में बुजुर्गों, असहायों और समाज के सबसे कमजोर वर्ग को आदर देना केवल कर्तव्य नहीं बल्कि हमारा धर्म माना गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी कोशिश है कि राज्य का कोई भी निर्धन परिवार, माताएं, बहनें या हमारे दिव्यांग साथी स्वयं को बेसहारा न समझें। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में अंत्योदय का संकल्प सिद्ध हो रहा है। इसी दिशा में राज्य सरकार भी गरीबों, वंचितों और कमजोर वर्गों के कल्याण में जुटी है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन सरकार के स्नेह, सम्मान और सुरक्षा का वचन है

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन केवल आर्थिक सहायता नहीं है, अपितु निर्धन परिवारों, दिव्यांग साथियों में आपके प्रति सरकार का स्नेह, सम्मान और सुरक्षा का वचन है। राज्य सरकार सभी को अपने परिवार का हिस्सा मानती है। सरकार प्रत्येक नागरिक के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कृषक कल्याण वर्ष में राज्य सरकार ने किसान हितैषी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रदेश के किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कर्ज दिया जाएगा और इसे चुकाने की समयावधि 31 मार्च नहीं होगी, बल्कि किसान जिस तारीख को कर्ज लेंगे.

10 साल में देश के 25 करोड़ से ज्यादा लोग बाहर आए गरीबी से

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश का प्रत्येक नागरिक स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 80 करोड़ से अधिक लोगों को हर महीने मुफ्त राशन मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान भारत, जल-जीवन मिशन, उज्जवला योजना जैसी योजनाओं ने जन-कल्याण का इतिहास लिखा है। सरकार गरीब, युवा, नारी और किसान कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आपदा में बचाव पर ब्रेल लिपि में प्रकाशित पुस्तक का किया लोकार्पण

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निश्शक्तजन के लिए आग, हीटवेब (लू) और आकाशीय बिजली से बचाव के संबंध में ब्रेललिपि में प्रकाशित पुस्तक का गुरूवार को मंत्रालय में लोकार्पण किया। पुस्तक का मुद्रण आपदा प्रबंध संस्थान भोपाल द्वारा सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सहयोग से कराया गया है। केरल और असम के बाद निश्शक्तजन के लिए आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में इस तरह की पहल मध्यप्रदेश द्वारा की गई है।

वेनेजुएला में 39 सेकेंड में भूकंप के 2 बड़े झटके

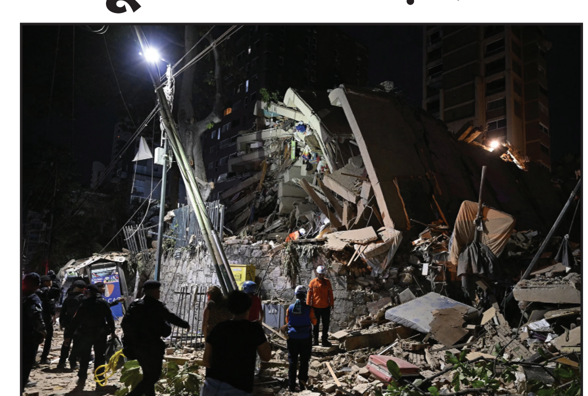

60 सेकेंड तक शहर हिलता रहा, अब तक 164 की मौत, 971 घायल

कराकस, वेनेजुएला। वेनेजुएला में 39 सेकेंड में दो ताकतवर भूकंप से तबाही मच गई है। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में बुधवार शाम 6.04 बजे 7.2 और 6.05 बजे 7.5 तीव्रता के दो झटके आए। उस समय भारत में गुरुवार तड़के 3.34 और 3.35 बजे थे। लोगों ने बताया कि भूकंप के बाद 60 सेकेंड तक शहर हिलता रहा। 20 ऑफ्टरशॉक भी दर्ज किए गए हैं। अब तक 164 मौतों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 971 घायल हैं। ये भूकंप ऐसे दिन आए, जब पूरे देश में राष्ट्रीय अवकाश था। 1821 में स्पेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई की ऐतिहासिक जीत की सालगिरह पर स्कूल और दफ्तर बंद थे।

मानसून सत्र तक टल सकता है...मंत्रिमंडल विस्तार, दो-तिहाई बहुमत जुटाने पर निगाह

नई दिल्ली, एजेंसी

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में देरी की संभावना है। माना जा रहा कि इसके लिए सरकार मानसून सत्र खत्म होने तक इंतजार करेगी। फिलहाल सरकार की निगाहें संविधान संशोधन विधेयक के लिए दो तिहाई बहुमत जुटाने और तृणमूल कांग्रेस समेत कुछ दलों में हुई टूट के किसी निष्कर्ष पर पहुंचने पर है। गौरतलब है कि मंगलवार को पीजे कुरियन के मंत्री पद से इस्तीफे व प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति से मुलाकात के कारण विस्तार की अटकलों को बल मिला था। सूत्र के मुताबिक अभी सरकार का सारा ध्यान जुलाई के तीसरे सप्ताह में शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र पर है। इस सत्र में सरकार की कोशिश महिला आरक्षण व परिसीमन के लिए जरूरी दो तिहाई बहुमत जुटाने पर है। इसके लिए सरकार ऐसे गैरकांग्रेसी दलों के लगातार संपर्क में है, जिन्होंने बजट सत्र में संविधान संशोधन बिल का विरोध किया था। सूत्र ने बताया कि इस क्रम में तृणमूल, शिवसेना यूबीटी, आप के संसदीय दल में टूट से सरकार को बल मिला है। वाईएसआरसी, बीआरएस और द्रमुक जैसे दलों से भी सहयोग के लिए बातचीत जारी है।

पीएम मोदी ने मंत्रालयों के बीच तालमेल पर दिया जोर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अलग-अलग विभागों और मंत्रालयों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया और नीट-यूजी के दोबारा सफल आयोजन के लिए किए गए समन्वित प्रयासों को सराहा। मोदी ने कहा, मंत्रालयों के बीच बिना किसी रुकावट व तालमेल के साथ काम करना ही किसी भी चुनौती से निपटने की गारंटी है। पश्चिम एशिया संकट के दौरान भी, पीएम ने अलग-अलग मंत्रालयों के बीच तालमेल के महत्व पर जोर दिया था।

संगठन की नई टीम पर अंतिम मंथन बाकी

मंत्रिमंडल विस्तार में भले ही देरी संभव है, मगर भाजपा की केंद्रीय टीम जुलाई के पहले सप्ताह तक घोषित हो सकती है। इस संदर्भ में कई दौर की माथापच्ची के बाद एक सूची तैयार की गई है। इस सूची पर अंतिम मंथन के बाद नई टीम घोषित कर दी जाएगी।

ट्रक में घुसी कार

औरंगाबाद के चार लोगों की मौत

एक घंटे फंसे रहे; मंदसौर में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर हादसा

मंदसौर। मंदसौर में दिल्ली-मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस-वे पर एक तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी। हादसे में कार सवार चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दुर्घटना गुरुवार सुबह करीब 11 बजे हुई।सीतामऊ थाना पुलिस के मुताबिक, रेनॉल्ट ट्राइबर कार में छह लोग सवार थे। सभी महाराष्ट्र के औरंगाबाद के रहने वाले हैं। वे दिल्ली मोबाइल इक्विपमेंट का सामान लेने जा रहे थे, लेकिन इस बीच तितरोद में हादसे का शिकार हो गए।

भारत का बड़ा फैसला

बांग्लादेशी नागरिकों के लिए फिर शुरू होगी टूरिस्ट वीजा सेवा

नई दिल्ली। भारत ने लगभग दो साल बाद बांग्लादेशी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा सेवा फिर से शुरू करने का फैसला किया है। भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने गुरुवार को घोषणा की कि 28 जून से बांग्लादेश के पांच वीजा आवेदन केंद्रों के जरिए सामान्य टूरिस्ट वीजा आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इससे पहले सुरक्षा कारणों के चलते भारतीय उच्चायोग ने वीजा संबंधी गतिविधियों को सीमित कर दिया था। भारतीय वीजा आवेदन केंद्र में घोषणा करते हुए दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि उन्हें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि टूरिस्ट वीजा के लिए सामान्य आवेदन प्रक्रिया दोबारा शुरू की जा रही है। इसके तहत रविवार 28 जून 2026 से आवेदन जमा किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि मानवीय आधार पर मेडिकल वीजा की सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी।

भारत ने बांग्लादेशियों के लिए टूरिस्ट वीजा फिर शुरू की

- 28 जून से फिर शुरू होगी टूरिस्ट वीजा सेवा।
- आवेदन ढाका समेत पांच वीजा केंद्रों पर लिए जाएंगे।

अगस्त 2024 में भारतीय प्रतिष्ठानों पर हमलों के बाद वीजा सेवाएं की गई थीं सीमित।

पांच केंद्रों से शुरू होगी सेवा

उन्होंने बताया कि शुरुआती चरण में ढाका, राजशाही, चटगांव, सिलहट और खुलना स्थित पांच वीजा केंद्रों से टूरिस्ट वीजा जारी किए जाएंगे। भविष्य में इस व्यवस्था का और विस्तार किया जाएगा। त्रिवेदी ने उम्मीद जताई कि इस कदम से दोनों संप्रभु देशों के लोगों के बीच आपसी संबंध और मजबूत होंगे। ढाका में नियुक्त भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने गुरुवार को बंगभवन में बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपना परिचय पत्र सौंपा।

दिल्ली रेप-मर्डर का आरोपी नपुंसक

नई दिल्ली। दिल्ली में 11 साल की बच्ची के रेप-मर्डर को लेकर नया दावा किया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी कैब ड्राइवर बासू कुमार सिंह (29) इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यानी शारीरिक संबंध बनाने में दिक्कत आने से पीड़ित था। उसकी नपुंसकता रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है।पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने पूछताछ में कबूल भी किया है। उसने बताया कि बच्ची के साथ कार की पिछली सीट पर रेप करने की कोशिश की लेकिन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कारण ऐसा नहीं कर सका। आरोपी ने बताया कि उसने बच्ची को शोर मचाने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। फिर उसे फरीदाबाद-गुरुग्राम सीमा के पास एक सुनसान जंगली इलाके में ले गया और उसकी हत्या कर दी और शव को पत्थरों के ढेर के नीचे छिपा दिया। आरोपी कैब ड्राइवर बिहार के खगड़िया का रहने वाला है। उसकी पत्नी खुशबू देवी का दावा है कि बासू से उसकी शादी 7 साल पहले हुई थी।

रिपोर्ट पॉजिटिव आई, बोला- रेप नहीं कर सका, फिर हत्या की; पत्नी ने कहा- हमारे 2 बेटे हैं

चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई, बुजुर्गों की सेहत पर हो रही भारी लापरवाही

भारत में हर साल फ्लू से 1.2 लाख मौतें, टीका लेने वाले 2 प्रतिशत भी नहीं

नई दिल्ली (एजेंसी)

भारत में बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। 'जर्नल ऑफ द इंडियन एकेडमी ऑफ गेरियाट्रिक्स' में छपे विशेषज्ञों के एक नए अध्ययन के अनुसार देश में हर साल इन्फ्लूएंजा (फ्लू) के कारण लगभग 1.2 लाख लोगों की जान चली जाती है। हालांकि इस रिपोर्ट में ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें करीब दो-तिहाई लोग 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के होते हैं। इसके बाद भी देश के 2 प्रतिशत बुजुर्गों ने भी फ्लू से बचाव का टीका नहीं लगवाया है।

समझिए क्या कहते हैं आंकड़े?

रिपोर्ट में विशेषज्ञों ने 'लोंगीट्यूडल एजिंग स्टडी इन इंडिया' के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि बुजुर्गों में टीकाकरण की स्थिति बेहद दुखद है। रिपोर्ट के मुताबिक टिटनेस-डिप्टीरिया का टीका सिर्फ 2.75 प्रतिशत बुजुर्गों ने लगवाया है। हेपेटाइटिस बी का टीका केवल 1.82 प्रतिशत लोगों को मिला है। इन्फ्लूएंजा (फ्लू) की वैक्सीन महज 1.59 प्रतिशत बुजुर्गों तक पहुंची है। इतना ही नहीं चौंकाने वाली बात तो यह है कि निमोनिया से बचाने वाला न्यूमोकोकल वैक्सीन तो सिर्फ 0.74 प्रतिशत लोगों ने ही लिया है।

भारत में बुजुर्गों का टीकाकरण ना के बराबर

इस मामले में इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के मेडिसिन विभाग के डॉक्टर सुरनजीत चटर्जी का कहना है कि भारत में वयस्कों और बुजुर्गों का टीकाकरण न के बराबर है, जिसमें तुरंत सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाना सेहत में एक निवेश की तरह है। यह बुजुर्गों को संक्रमण और अस्पताल में भर्ती होने की नौबत से बचाता है। इसके लिए कई सरकारी और सामाजिक संस्थाओं को मिलकर काम करना होगा।

क्यों आ रही है यह नौबत

जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज के डॉ. सनी सिंघल और एम्स दिल्ली, जिपमेर पुडुचेरी व सीएमसी वेलोर जैसे बड़े संस्थानों के डॉक्टरों की टीम ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। उनके अनुसार इस लापरवाही की मुख्य वजहें हैं कि भारत में बुजुर्गों के टीकाकरण के लिए कोई एक तय राष्ट्रीय गाइड लाइन नहीं है। इसके साथ लोगों में जागरूकता की भारी कमी है और टीकों को लेकर लोगों में हिचकिचाहट, वैक्सीन की कीमत और आम लोगों तक इसकी आसान पहुंच न होना भी बड़ी बाधा के तौर पर है।

भारत में बुजुर्गों की बढ़ती आबादी

गौरतलब है कि भारत में बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। साल 2022 में कुल आबादी में बुजुर्गों (60 साल से ऊपर) की हिस्सेदारी 10.5 प्रतिशत थी, जिसके 2050 तक दोगुना होने का अनुमान है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भारत सरकार बुजुर्गों के लिए एक खास टीकाकरण नीति बनाए, तो असमय होने वाली मौतों और अस्पताल के खर्चों को काफी हद तक रोका जा सकता है। उन्होंने बुजुर्गों के लिए फ्लू, निमोनिया, दाद (शिंगल्स) और टिटनेस के टीकों को नियमित रूप से लगवाने की सलाह दी है।

संक्षिप्त समाचार

चार साल में छह गुना बढ़ा आनलाइन कारोबार : कैट

सतना। कन्फ़ेडरेशन आफ आल इंडिया टेंडर्स कैट म.प्र.के सचिव अशोक दौलतानी का कहना है कि शहरवासी शो रूम में जाने के बजाय घर बैठे मोबाइल, टी.वी., फ्रिज मंगा रहे हैं सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक आइटम का आर्डर किया जा रहा है। उसके बाद फैशन और किचन का सामान मंगाया जा रहा है। बीते चार सालों में आनलाइन कारोबार छः गुना तक बढ़ गया है। 2022 में आनलाइन कारोबार 3 हजार करोड़ का था 2026 में 18 हजार करोड़ पहुंचने का अनुमान है। यह दावा व्यापारियों की शीर्ष संस्था कन्फेडरेशन आफ आल इंडिया टेंडर्स कैट की रिपोर्ट में हुआ है। अशोक दौलतानी ने बताया कि कैट ने सरकार को आनलाइन व्यापार पर पत्र लिखकर चिंता व्यक्त की है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अनिल सिंह जिला महामंत्री (शहर) नियुक्त

सतना। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के संगठन विस्तार एवं पार्टी को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पार्टी नेतृत्व ने अनिल सिंह एडवोकेट को जिला महामंत्री (शहर), सतना पद पर नियुक्त किया है। विधि प्रकोष्ठ अध्यक्ष सुनीता मिश्रा, विधि प्रकोष्ठ सचिव रेखा दाहिया, विधि प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष मनीषा वर्मा तथा श्रम प्रकोष्ठ प्रभारी ऊषा चौधरी की सहमति से यह नियुक्ति संपन्न हुई। पार्टी पदाधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया है कि अनिल सिंह एडवोकेट के अनुभव, संगठनात्मक क्षमता एवं सक्रिय कार्यशैली से पार्टी को शहर स्तर पर और अधिक मजबूती मिलेगी तथा संगठन के जनाधार के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त होगा।

[व्यवसाय] 276 किसानों ने बेची 4777 क्विंटल उपज

हड़ताल के दूसरे दिन गुलजार रही मंडी

नगर संवाददाता ■ सतना

प्रदेश सरकार द्वारा मंडी टैक्स में बढोत्तरी किए जाने के फैसले के खिलाफ गल्ला कारोबारियों द्वारा मंगलवार को एक दिवसीय हड़ताल किया गया था। जिस वजह से मंगलवार को मंडी में कृषि उपज की नीलामी का काम नहीं हो सका था। बुधवार को काफी संख्या में किसानों ने मंडी पहुंच कर अपनी को बेचने का काम किया। हलांकि उपज की नीलामी अपने निर्धारित समय से करीब एक घंटे की देरी से शुरू हुई लेकिन शाम तक किसानों की उपज की नीलामी का काम पूरा हो गया। ज्ञात हो कि कृषि उपज मंडी सतना विन्ध्य क्षेत्र की इकलौती ए ग्रेड मंडी है। यही वजह है कि यहां पर जिले के अलावा आसपास के इलाकों से भी काफी संख्या में किसान अपनी उपज को बेचने के लिए आते हैं।

सर्वाधिक गेहूं की रही आवक

कृषि उपज मंडी में बुधवार को सर्वाधिक आवक गेहूं की रही। करीब 127 किसानों द्वारा 3हजार 6 सौ 22 क्टिल गेहूं लाया गया था जिसे व्यापारियों ने बोली लगाकर खरीदा। व्यापारियों द्वारा न्यूनतम भाव 2201 रुपए क्टिल एवं अधिकतम बोली 25478 रुपए क्टिल गलाई गई। इसी प्रकार से 35 किसानों द्वारा 258 क्टिल चना बेचा गया। चना का न्यूनतम भाव व्यापारियों ने 4805 रुपए व अधिकतम भाव 5695 रुपए क्टिल लगाया गया। वहीं 34 किसानों द्वारा 389 क्टिल सरसो बेचने का काम किया गया । व्यापारियों द्वारा सरसो का अधिकतम दाम 7490 रुपए लगाया गया जबकि मसूर बेचने के लिए मंडी में महज 19 किसान ही पहुंचे । किसानों ने करीब 154 क्टिल मसूर की उपज बेची। जिसका व्यापारियों न्यूतम भाव 5395 रुपए तो अधिकतम दाम 6060 रुपए क्टिल लगाया।

आगे भी हो सकती है हड़ताल!

प्रदेश सरकार द्वारा मंडी शुल्क को 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 1.5 प्रतिशत किए जाने के निर्णय का विरोध तेज हो गया है। ऐसे में अगर आने वाले दिनों में प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ाए गए टैक्स में कटौती नहीं की जाती है तो व्यापारियों द्वारा बड़ा आंदोलन किया जा सकता है। कृषि उपज मंडी के व्यापारिक संगठनों की माने तो व्यापारियों की मांग पर ही तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मंडी टैक्स दो प्रतिशत को घटा कर एक दशमलव 20 प्रतिशत किया गया था। अब अगर प्रदेश सरकार पुनः टैक्स को बढ़ाती है तो अपनी मांग को मनवाने के लिए व्यापारी पुनः बड़ा आंदोलन छेड़ सकते हैं।

निकाय की आय का 18 प्रतिशत एससी बहुल बस्तियों के विकास पर करें खर्च

■ आयोग अध्यक्ष ने नगरीय निकाय के अधिकारियों को दिए निर्देश

नगर संवाददाता ■ सतना

मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉ. कैलाश जाटव ने बुधवार को नगर पालिक निगम सतना कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में जिले के नगरीय निकायों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की तथा अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को मिल रहे लाभों की जानकारी प्राप्त की। डॉ. जाटव ने निर्देश दिए कि नगरीय निकाय अपनी स्वयं की आय का 18 प्रतिशत भाग अनुसूचित जाति बहुल बस्तियों के विकास कार्यों पर व्यय करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में सड़क, नाली, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होने पर डीमैट फंड से राशि प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए।

पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचे लाभ

आयोग अध्यक्ष ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचे तथा योजनाओं की नियमित समीक्षा एवं प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्वच्छता कर्मचारियों को सुरक्षा एवं स्वच्छता किट उपलब्ध कराने तथा उनका नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराने के निर्देश भी दिए।

नशा मुक्ति केन्द्र शुरू करें

बैठक के दौरान डॉ. जाटव ने नगर निगम को नशा मुक्ति केंद्र प्रारंभ करने पर विचार करने की सलाह दी। साथ ही महिला कर्मचारियों की पारिवारिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए उनकी ड्यूटी यथासंभव दोपहर बाद लगाने के निर्देश दिए, जिससे वे अपने बच्चों को विद्यालय भेजने एवं वापस लाने की जिम्मेदारी सुचारू रूप से निभा सकें।

ये रहे मौजूद

बैठक में नगर पालिक निगम सतना आयुक्त डॉ. शेर सिंह मीना, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग अरुण शुक्ला, स्वास्थ्य अधिकारी अरविंद प्रताप सिंह, योजना प्रभारी दीपक शर्मा, सतना जिलान्तर्गत सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी के साथ नगर पालिक निगम सतना की योजना शाखा के अधिकारी उपस्थित रहे।

गेहूं खरीदी केंद्र में हो रही अनियमितता से ग्रामीणों में आक्रोश : विपिन सिंह

नगर संवाददाता ■ सतना

किसान अधिकार संघर्ष समिति के संरक्षक विपिन सिंह का आरोप है कि सेवा सहकारी समिति चूंद में पदस्थ अधिकारियों की मनमानी से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है, सेवा सहकारी समिति चूंद के किसान और किसान अधिकार संघर्ष समिति के संरक्षक विपिन सिंह ने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा की सेवा सहकारी समिति चूंद के नाम से दो-दो खरीदी केंद्र बनाए गए जो कोटर के आस-पास थे। गांव में सहकारी गोदाम चालीस वर्ष पूर्व से स्थापित कार्यालय केंद्र होने के बावजूद भी गांव में खरीदी केंद्र ना बनाकर अपने आप को लाभ पहुंचाने के लिए अपनी सुविधा की दृष्टि से केंद्र बनाए जाते है गांव में लगभग तीन सौ सेवा सहकारी समिति चूंद से पंजीकृत किसान हैं। गेहूं बेचने के लिए दस किलोमीटर दूर जाते हैं गांव में न खाद, न बीज न गेहूं की खरीदी होती और न ही पूर्व कलेक्टर के उस आदेश का पालन किया जाता जो किसान अधिकार संघर्ष समिति के संघर्ष और मांग के बाद कम से कम दो दिन चूंद कार्यालय संचालित करने का एक नया आदेश दिया गया था। गांव वालों का आरोप है की सेवा सहकारी समिति के अधिकारियों कर्मचारियों की वजह से हमारे गांव चूंद को सिर्फ भ्रष्टाचार से बदनामी मिलती है, गांव का नाम खराब होता है जहां गांव की प्रशंसा लोग सर्वाधिक सैनिक बहुलता और शहीदी गांव के लिए करते हैं वहां गेहूं खरीदी में समिति में हुआ भ्रष्टाचार हम चूं द वाशियो को आहत करता है जल्द ही हम सब लोग कलेक्टर और सहकारिता उपायुक्त को मिल कर अपनी पीड़ा बताएंगे और किसान अधिकार संघर्ष समिति के बैनर तले अपने अधिकार की मांग करेंगे।

पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता के जन्मदिवस पर वैश्य महासम्मेलन ने किया सेवा कार्य

नगर संवाददाता ■ सतना

वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश के संरक्षक एवं मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता के जन्मदिवस के अवसर पर वैश्य महासम्मेलन द्वारा जिला अस्पताल परिसर में सेवा संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अस्पताल में भर्ती मरीजों एवं उनके परिजनों को भोजन एवं मिष्ठान वितरित कर जन्मदिवस को सेवा कार्यों के माध्यम से मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान वैश्य महासम्मेलन के पदाधिकारियों ने अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों के बीच भोजन वितरण किया तथा उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की।

वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी श्याम लाल गुप्ता 'श्यामू' ने कहा कि मध्य प्रदेश में वैश्य महासम्मेलन समाज का एक मजबूत और संगठित स्तंभ बनकर कार्य कर रहा है। संगठन सामाजिक सेवा, जनकल्याण और समाज के उत्थान के लिए निरंतर सक्रिय भूमिका निभा रहा है।इस अवसर पर जिला अस्पताल परिसर में भर्ती मरीजों एवं उनके परिजनों के बीच भोजन और मिष्ठान का वितरण किया गया।इस दौरान वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश उपाध्यक्ष हरिओम गुप्ता, अशोक अग्रवाल जय प्रताप गुप्ता अशोक गुप्ता, वैश्य महासम्मेलन प्रदेश सह मीडिया प्रभारी श्याम लाल गुप्ता श्यामू , सुरेश बड़ेरिया मनोज कटारे राजीव गुप्ता बबलू राजकुमार अग्रवाल टिंकू, जितेन्द्र साहू जय अग्रवाल मनोज अग्रवाल ,श्रीनाथ गुप्ता, जगदीश कश्यप ,गणेश गुप्ता, जेपी गुप्ता, मोहित अग्रवाल, दुर्गेश कश्यप, बलराम गुप्ता, रामजी गुप्ता, रवि गुप्ता, अमित गुप्ता, गौरव गुप्ता ,रामावतार अग्रवाल, मधुकर पारेख अन्नू अग्रवाल सहित उपस्थित रहे।

शीघ्र पेयजल समस्या का समाधान नहीं हुआ तो गरीब सेना करेगी जनांदोलन

■ गुणवत्ताहीन पेयजल आपूर्ति कर शहरवासियों के स्वास्थ के साथ खिलवाड़ कर रहा है नगर निगम

नगर संवाददाता ■ सतना

गरीब सेना का प्रतिनिधि मंडल 26 जून को सुबह 11 बजे शहर कई के वार्डों में व्याप्त पेयजल संकट के समाधान एवं नगर पालिक निगम सतना के वेपरवाह, बेखौफ कमिश्नर शेर सिंह मीणा की दादागिरी एवं तानाशाही रवैया के विरोध में कलेक्टर से मिलकर शिकायत दर्ज कराएगा। पेयजल समस्या का समाधान नहीं हुआ तो व्यापक स्तर पर जनांदोलन किया जाएगा। गरीब सेना के मित्र एवं नगर पालिक निगम सतना के पूर्व पार्षद महिंद वर्धन सिद्धार्थ पप्पू ने कहा है कि नगर निगम का मुख्य जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी शहरवासियों को यदि साफ एवं शुद्ध पीने का पानी मुहैया नहीं करा सकता है ,तो उसे पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि आयुक्त के संरक्षण के चलते लापरवाह पेयजल प्रभारियों द्वारा शहर के कई वाडों में नियमित एवं शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नहीं की जा रही है। शहर के ऐसे कई वार्ड एवं मुहल्लें हैं जहां पेयजल आपूर्ति की गंभीर समस्या बनी हुई है। जिसमें वार्ड 18 सोंधियां मुहल्ला, वार्ड 15 मंगल भवन के उत्तर, वार्ड 17 हाउसिंग बोर्ड कालोनी शामिल हैं। जहां पेयजल आपूर्ति होती भी है तो बिना मोटर पंप के पानी नहीं मिल पाता है।

कई वाडों में मटमैला दुर्गंधयुक्त पीने का पानी सप्लाई धड़ल्ले से किया जाता है, जो आम नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। पूर्व पार्षद ने कहा कि नई बस्ती जोन 4 के पेयजल प्रभारी इंजी. विद्या निवास वागरी एवं उनके सहयोगी कर्मचारी बेहद लापरवाह हैं।

वैश्विक ज्ञान-साझेदारी की दिशा में एकेएस का महत्वपूर्ण कदम

नगर संवाददाता ■ सतना

नैक एक्रेडिटेड एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से मान्यता प्राप्त एकेएस विश्वविद्यालय, सतना ने वैश्विक शैक्षणिक उत्कृष्टता, अनुसंधान एवं नवाचार को नई गति प्रदान करते हुए शिनावात्रा विश्वविद्यालय, थाईलैंड के साथ एक दूरदर्शी अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञान-साझेदारी, वैश्विक शैक्षणिक संवाद तथा भविष्य उन्मुख शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इस अंतरराष्ट्रीय सहयोग पहल का सफल समन्वयन प्रबंधन अध्ययन संकाय के अधिष्ठाता डॉ. कौशिक मुखर्जी द्वारा किया गया। इस अवसर पर एकेएस विश्वविद्यालय के प्रति-कुलाधिपति इंजी. अनंत कुमार सोनी, कुलपति प्रो. बी. ए. चोपड़े, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के निदेशक प्रो. जी. सी. मिश्रा सहित विश्वविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षाविद् एवं अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं शिनावात्रा विश्वविद्यालय की ओर से विश्वविद्यालय के अध्यक्ष तथा वरिष्ठ प्राध्यापकों के प्रतिनिधिमंडल ने सहभागिता की।

सहयोग समझौते के अंतर्गत दोनों विश्वविद्यालयों ने संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं, शिक्षक एवं विद्यार्थी आदान-प्रदान कार्यक्रमों, नवाचार एवं उद्यमिता संवर्धन, कौशल विकास, बहुविषयी अध्ययन तथा उभरती प्रौद्योगिकियों पर आधारित शिक्षण और प्रशिक्षण गतिविधियों को प्रोत्साहित करने पर सहमति व्यक्त की। विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आँकड़ा विज्ञान, डिजिटल नवाचार तथा उद्योग-शिक्षा समन्वय के क्षेत्रों में दीर्घकालिक सहयोग की व्यापक रूपरेखा निर्धारित की गई।

आज रखे गये इमामबाड़ों में ताजिया, निकली सवारियां, हुआ अलाव

सतना। मोहर्रम की 8 तारीख बुधवार की रात्रि शहर के खूंथी और नजीराबाद मोहल्ले से झूले और मेहंदी निकाली गई। यह जुलूस धवारी चौराहा होते हुए सिटी कोतवाली, बसीरन मोहल्ला, कंपनी बाग, पन्नी लाल चौक होता हुआ देर रात अपने मुकाम पर पहुंचा। गौरतलब है कि इमाम हुसैन के छह महीने के मासूम बेटे अली असगर की शहादत की याद में झूले निकाले जाता हैं। गुरुवार की रात्रि शहर के सभी इमामबाड़ों में ताजिया रखी जाएगी। आज रात शहर के अलग-अलग मोहल्लों से सवारियां उठेंगी , जो कि शहर गश्त करते हुए इमामबाड़ों पर सलामी देंगे। कई स्थानों पर अलाव का आयोजन भी किया गया ।

अहंकार बनता है मनुष्य के पतन का कारण : ओमजी महाराज

नगर संवाददाता ■ सतना

शहर के रामना टोला स्थित समाजसेवी विश्वनाथ नेमा के निवास पर आयोजित श्री श्रीमद् भागवत कथा में पोड़ी धाम मैहर के ओमजी महराज ने कथा के तीसरे दिन सती चरित्र व ध्रुव चरित्र की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि श्रीमद्भागवत एवं पुराणों में वर्णित सती चरित्र त्याग, पतिव्रता धर्म और भगवान शिव के प्रति अटूट समर्पण का अद्भुत प्रसंग सुनाया । प्रजापति दक्ष की पुत्री सती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार किया था। दक्ष को शिवजी का वैरागी स्वरूप पसंद नहीं था, इसलिए वे उनसे द्वेष रखते थे। एक बार दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और जानबूझकर शिवजी तथा सती को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन सती अपने पिता के घर जाने की इच्छा से यज्ञस्थल पहुंच गईं। दक्ष ने शिवजी के प्रति कटु वचन कहे और उनका अपमान किया। पति का अपमान सती से सहन नहीं हुआ। उन्होंने सभा में उपस्थित लोगों को धर्म का उपदेश देते हुए कहा कि जो व्यक्ति भगवान शिव जैसे महापुरुष का अपमान करता है, उसका कल्याण नहीं हो सकता। इसके बाद सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब यह समाचार शिवजी को मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न कर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कराया। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार मनुष्य के पतन का कारण बनता है, जबकि श्रद्धा, समर्पण और मर्यादा जीवन को महान बनाते हैं। इसके अलावा कथा वाचक ओमजी महराज ने ध्रुव चरित्र की कथा भी सुनाई।

इस भागवत कथा को सुनने के लिए पूर्व महापौर राजा राम त्रिपाठी, पूर्व नगर निगम अध्यक्ष अनिल जायसवाल,भाजपा नेता रविन्द्र सेठी, नीरज शुक्ला, डा.आर के नेमा, प्रीति नेमा, डा.राजेंद्र नायक, राजेश दुबे, दिनेश दुबे एडवोकेट के अलावा काफी संख्या में श्रद्धालुजन उपस्थित रहे।

कवि तेज भान सिंह तेज को मिली पीएचडी की उपाधि

सतना। कवि तेज भान सिंह जो विट्स महाविद्यालय में हिंदी के सहायक प्राध्यापक हैं। उन्हें उनके शोध शीर्षक 'प्रहलाद अग्रवाल के सिनेमा संबंधी लेखन का विवेचनात्मक अध्ययन' विषय पर अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। उन्होंने अपना शोध कार्य हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉ दिनेश कुशवाह एवं शोध निदेशक डॉ सुरेंद्र बहादुर सिंह चौहान के निर्देशन में पूर्ण किया। उन्होंने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय विट्स ग्रुप के चेयर मैन सुनील सेनानी, एचआर हेड श्रीमती निवेदिता मिश्रा, प्रमोद पाण्डेय वा पूरे विट्स परिवार के साथ-साथ अपने साहित्यकारों में अनूप अशेष, छोटेलाल पांडे, रामनरेश तिवारी और अपने पूज्य माता एवं पिता को दिया।

[समस्या] सड़क, सफाई व पेयजल समस्याओं पर उठे सवाल

शहर की बदहाल व्यवस्था से जनता परेशान

नगर संवाददाता ■ सतना

शहर में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर पूर्व पार्षद प्रकाश चौरसिया ने नगर निगम प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा है कि नागरिक सड़क, सफाई और पेयजल जैसी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीवर लाइन कार्य के लिए खोदी गई सड़कों को कई स्थानों पर अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे आमजन को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें इतनी खराब हो चुकी हैं कि राहगीरों और वाहन चालकों को दुर्घटना का खतरा बना रहता है। कई स्थानों पर दुकानदार स्वयं पानी का छिड़काव और कुटाई कराकर सड़क को व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है।

पूर्व पार्षद ने कहा कि सड़कों के किनारे पड़ा कचरा समय पर नहीं उठाया जा रहा है। दोपहर तक कचरे के ढेर पड़े रहने से जहां बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ रहा है, वहीं आवारा मवेशी कचरे के आसपास जमा होकर लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। कई बार मवेशियों की आपसी लड़ाई में राहगीर भी घायल हो जाते हैं।

उन्होंने विशेष रूप से मंदिर मार्गों की सफाई व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कहा कि श्रद्धालुओं की भावनाओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। जैन मुनि महाराज एवं साध्वी माताओं को कचरे के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। वहीं मंगलवार और शनिवार को शहर के प्रतिष्ठित हनुमान चौक स्थित हनुमान मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और प्रसाद अर्पित करने पहुंचते हैं, जिन्हें असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। पेयजल व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि टूटी-फूटी सड़कों के कारण कई स्थानों पर पाइपलाइनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इससे गंदा पानी पाइपलाइन में मिल जाने की आशंका बनी रहती है, जिससे लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

पूर्व पार्षद प्रकाश चौरसिया ने नगर निगम प्रशासन से सड़क मरम्मत, नियमित कचरा उठाव तथा पेयजल व्यवस्था में सुधार की मांग करते हुए कहा कि यदि महापौर चाहें तो रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था भी लागू की जा सकती है, जिससे सुबह शहर साफ-सुथरा दिखाई देगा और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।

दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में भागवत कथा का शुभारंभ

■ निकली कलश यात्रा, भक्ति संगीत के साथ कथा का शुभारंभ

नगर संवाददाता ■ सतना

दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, पुरानी कचहरी प्रांगण में श्रीमद्भागवत कथा का विशेष आयोजन श्रद्धा एवं भक्ति भाव के साथ प्रारंभ हुआ। इस शुभ अवसर पर मास्टर प्लान गली नंबर-4 स्थित मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं मातृशक्ति शामिल हुईं। कलश यात्रा में पंडित ओंकार प्यासी, सुबोध अग्रवाल, रामशंकर, रंजीत द्विवेदी, प्रदीप दहिया, अमित तिवारी, कान्हा गौतम, विजय सिंह बागरी, विकास तिवारी सहित अनेक श्रद्धालुओं ने सहभागिता निभाई।

कार्यक्रम में नेकी फाउंडेशन परिवार की ओर से बृजेश शुक्ला, श्रीमती शालिनी सिंह, श्रीमती निधि सिंह कपूर, डॉ. आकांक्षा कपूर धवन, अमायरा धवन, प्रिशा धवन, मोहित सिंह कपूर, अमित भावनानी एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

कलश यात्रा के पश्चात दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में भक्ति संगीत के साथ कथा का शुभारंभ हुआ। कथा प्रारंभ होने से पूर्व पंडित जी द्वारा अध्यात्म एवं धर्म से जुड़े विभिन्न विषयों पर प्रेरणादायक प्रवचन दिए गए। श्रद्धालुओं ने कथा एवं प्रवचन का श्रवण कर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया।

संक्षिप्त समाचार

सिरमौर पुलिस ने निकाली सायबर जागरूकता रैली

रीवा। देश और प्रदेश मे बढ़ते साइबर अपराधों से बचाव के लिए सेफ क्लिक अभियान-26 साइबर जागरूकता अभियान की शुरुआत की गयी है। सिरमौर थाना प्रभारी दीपक तिवारी द्वारा साइबर सुरक्षा संबंधी जानकारी प्रदान की जा रही है। छात्र छात्रों एवं नागरिकों को ऑनलाइन ठगी, फर्जी लिंक, ओटीपी साझा करने के खतरे, सोशल मीडिया फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, निवेश धोखाधड़ी, साइबर बुलिंग एवं अन्य साइबर अपराधों से बचाव के उपायों के बारे में जागरूक किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि वर्तमान समय में साइबर अपराधों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए प्रत्येक नागरिक को डिजिटल माध्यमों का सुरक्षित उपयोग करना आवश्यक है। किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं।अभियान के दौरान स्कूली बच्चों के हाथों मे पोस्टर, पम्पलेट, जनसंवाद, सोशल मीडिया संदेश एवं जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों तक साइबर सुरक्षा का संदेश पहुंचाया जा रहा है।

पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ÷ ¦कÖ¦ संबोधित

रीवा। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय अटल कुंज रीवा में आपातकाल लगाए जाने के 51 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में संविधान हत्या दिवस का आयोजन किया गया ।25 जून 1975 को देश के संविधान की हत्या कर आपातकाल लगाया गया था आपातकाल की विभीसिका को प्रगट करने वाली प्रदर्शनी भी कार्यालय में लगाई जाएगी आपातकाल पर आयोजित विचार गोष्ठी को मुख वक्त के रूप में भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संबोधित किया वहीं विशिष्ट अतीत के रूप में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा उपस्थित रहे,कार्यक्रम की अध्यक्षता रीवा भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता ने की।गोष्ठी 3.30 बजे भाजपा कार्यालय में आयोजित की गई ।इस अवसर पर संभाग भर के मीशाबंधियों को सम्मानित भी किया गया।विचार गोष्ठी में रीवा जिले के सभी आम जनों पार्टी कार्यकर्ताओं सामाजिक कार्यकर्ताओं से पहुंचने की अपील भाजपा जिला महामंत्री उमाशंकर पटेल विवेक गौतम जीवनलाल साकेत ने की।

विजय बने सवर्ण अधिकारी कर्मचारी संगठन के जिला अध्यक्ष

रीवा। सामाजिक समरसता, कर्मचारी हितों की सुरक्षा और संगठनात्मक सशक्तिकरण के उद्देश्य से कार्यरत सवर्ण अधिकारी एवं कर्मचारी संगठन, मध्यप्रदेश ने अपने संगठन विस्तार अभियान के अंतर्गत रीवा जिले में नई जिम्मेदारी सौंपते हुए विजय तिवारी को जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। यह मनोनयन प्रदेश अध्यक्ष इंजी. अजय तिवारी द्वारा संगठन के संविधान में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है। 23 जून 2026 को जारी मनोनयन पत्र के अनुसार मनगवां थानान्तर्गत ग्राम तिवरिगवां निवासी विजय तिवारी को संगठन की जिला इकाई रीवा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति आगामी तीन वर्षों तक प्रभावशील रहेगी।

निगमायुक्त ने स्वच्छता व्यवस्था को प्रभावी बनाने ली समीक्षा बैठक

पहड़िया स्थित प्लांट में बाहर से कचरा लाये जाने पर जतायी नाराजगी

÷Uø संवाददाता ■ रीवा

निगम आयुक्त अक्षत जैन ने शहर की स्वच्छता व्यवस्था को अधिक प्रभावी एवं व्यवस्थित बनाने के संबंध में बुधवार को निगम सभागार में स्वच्छता विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में निगमायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि नगर निगम की स्वास्थ्य टीम एवं कार्यरत एजेंसियां बेहतर समन्वय के साथ कार्य करें तथा शहर की सफाई व्यवस्था को शत-प्रतिशत दुरुस्त करें। उन्होंने रैमकी कंपनी को डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण के लिए प्रभावी एवं व्यवहारिक रूट मैप तैयार कर शहर के प्रत्येक घर से कचरा संग्रहण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निगमायुक्त ने पुराने शहर सहित उन सभी वार्डों की सूची तैयार कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, जहां संकरी गलियों के कारण कचरा संग्रहण वाहन नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैनुअल सफाई कार्य में लगे कर्मचारियों के लिए छोटे रिक्शा वाहन अथवा हैंडकार्ट की व्यवस्था के संबंध में एक सप्ताह के भीतर विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाए तथा वैकल्पिक वाहन डिप्लॉय किए जाएं। निगमायुक्त ने पहड़िया स्थित वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट में बाहर से कचरा लाए जाने की नियमित शिकायतों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि अनुबंध में निर्धारित 28 नगरीय निकायों के अतिरिक्त अन्य किसी भी क्षेत्र का कचरा प्लांट में नहीं लाया जाए। उन्होंने प्लांट परिसर में डंप कचरे का शीघ्र प्रोसेसिंग कर लैंडफिल क्षेत्र को खाली कराने के निर्देश दिए।

मानस भवन नजदीक ट्रांसफार स्टेशन को स्थानान्तरित करने के निर्देश

बैठक के दौरान मानस भवन के पास स्थित ट्रांसफर स्टेशन को जल्द से जल्द स्थानांतरित करने के निर्देश देते हुए निगमायुक्त ने कहा कि खैरी में निर्माणाधीन ट्रांसफर स्टेशन के पूर्ण होने तक मानस भवन क्षेत्र में एकत्रित कचरे का तत्काल उठाव कर उसे सीधे जायो एवं कंटेनरों में डंप कर पहड़िया प्लांट भेजा जाए। साथ ही पुराने एवं जर्जर कचरा संग्रहण वाहनों को रिप्लेस करने के निर्देश दिए। निगमायुक्त ने इंडिपेंडेंट इंजीनियर के कार्यों की समीक्षा करते हुए नगर निगम अधिकारियों को उनकी वार्डों एवं प्लांट में नियमित उपस्थिति की जानकारी प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने पहड़िया प्लांट में स्थापित सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस नगर निगम कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। बैठक के अंत में निगमायुक्त ने सख्त निर्देश दिए कि तीनों एजेंसियां अपने-अपने स्कोप ऑफवर्क के अनुसार आपसी समन्वय बनाकर कार्य करें।

रीवा। रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में रीवा अपने बढ़ते क्रम में है। आने वाले दिनों में रीवा से मिर्जापुर(व्हाया हनुमना) रेल लाइन का काम शुरू होने की संभावना है। रीवा सांसद जनार्दन मिश्र केन्द्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से मुलाकात कर रीवा से मिर्जापुर रेल लाइन को शीघ्र प्रारंभ किये जाने के संबंध में वार्तालाप किये।

शहादत की रात को चौकी पर रखे गÖे ताजिया

रीवा। इस्लाम धर्म के आखिरी पैगम्बर हज़रत मुहम्मद सल्ललाहो अलैहे वसल्लम के नवासे शहीदे आज़म हज़रत इमाम हुसैन रजिअल्लाह तआला अन्हो की याद मे मनाये जाने वाले मोहर्रम की 08 तारीख को गत रात पचमठा घोघर स्थित वसीम उर्फ मून के घर से मेहंदी उठाई गई जो पचमठा मार्ग एस.के. स्कूल के पीछे से गस्त करती हुई शाहभोलन सिटी कोतवाली गई तथा फिर वहां से फोर्ट रोड स्थित हज़रत मुनौवर शाह बाबा के आस्ताने अशोक के पेड़ के पास हाजरी देती हुई उसी मार्ग से अयाज अली चौक होकर घोघर तकिया मे हज़रत मकबूल शाह दाता रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर गई तथा फिर वहां से अपने मुकाम को वापस हो गई।

साइबर ठगी के खिलाफ पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च

÷Uø संवाददाता ■ मनगवां

जिले में बढ़ते साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने और आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से रीवा पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक गुरकरन सिंह के निर्देशन में मनगवां में व्यापक साइबर जागरूकता फ्लैग मार्च एवं जनजागरूकता रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (एसडीओपी) प्रतिभा शर्मा के मार्गदर्शन में किया गया। इस दौरान थाना प्रभारी निरीक्षक पुष्पेन्द्र मिश्रा पुलिस बल, विभिन्न विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों, समाजसेवियों तथा स्कूली छात्र-छात्राओं के साथ जागरूकता रैली में शामिल हुए। रैली मनगवां थाना परिसर से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार, नगर परिषद क्षेत्र एवं प्रमुख मार्गों से गुजरी। प्रतिभागियों ने साइबर अपराध से बचाव संबंधी स्लोगन लिखे बैनर और तख्तियां लेकर लोगों को जागरूक किया। रैली के दौरान नागरिकों को ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, लिंक और साइबर अपराधियों के नए-नए हथकंडों के बारे में जानकारी दी गई।

अनजान व्यक्ति को न दें ओटीपी, बैंकिंग जानकारीः पुष्पेन्द्र मिश्रा

इस अवसर पर थाना प्रभारी निरीक्षक पुष्पेन्द्र मिश्रा ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि साइबर ठग बेहद शातिर होते हैं और लोगों को विभिन्न प्रलोभन देकर ठगी का शिकार बनाते हैं। ऐसे में किसी भी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, बैंकिंग जानकारी, पासवर्ड या अन्य गोपनीय जानकारी साझा न करें। किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें और लालच भरे ऑफरों के झांसे में न आएं। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार हो जाता है तो वह तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराए। उन्होंने कहा कि ठगी की घटना के बाद पहला एक घंटा ÷गोल्डन ऑवर÷ होता है। इस दौरान शिकायत दर्ज होने पर ठगी गई राशि को रोकने या वापस दिलाने की संभावना काफी बढ़ जाती है।पुलिस अधिकारियों ने कहा कि साइबर अपराध के खिलाफ जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है और आमजन की सतर्कता से ही ऐसे अपराधों पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है।

रबर बॉय आदर्श को जेल महानिदेशक ने किया सम्मानित

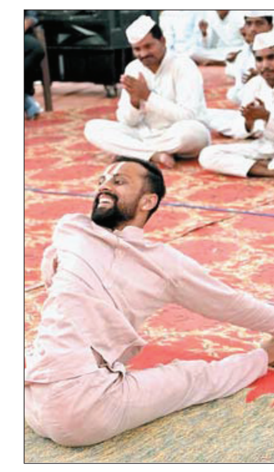

÷Uø संवाददाता ■ रीवा

रीवा जिले के युवा योग साधक एवं रबर बॉय के नाम से प्रसिद्ध आदर्श पांडे ने मध्य प्रदेश की योग प्रतिभा को एक बार फिर गौरवान्वित किया है। मध्य प्रदेश के वर्तमान जेल महानिदेशक वरूण कपूर के समक्ष आदर्श पांडे ने कठिन एवं आकर्षक योग आसनों का प्रदर्शन किया, जिसे देखकर डीजी वरुण कपूर ने उनकी प्रतिभा की खुलकर सराहना की। वरुण कपूर वर्तमान में मध्य प्रदेश जेल विभाग के महानिदेशक हैं। केंद्रीय जेल रीवा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आदर्श पांडे द्वारा किए जा रहे निःशुल्क योग सेवा कार्यों की प्रशंसा करते हुए सम्मानित किया। इस अवसर पर केंद्रीय जेल रीवा के अधीक्षक सतीश कुमार उपाध्याय की भी सराहना करते हुए डीजी वरुण कपूर ने कहा कि ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को मंच और प्रोत्साहन देना समाज के लिए प्रेरणादायक कार्य है। आदर्श पांडे वर्षों से योग के प्रचार-प्रसार में सक्रिय हैं और अपनी अनूठी योग कला के माध्यम से युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और समाजसेवा की भावना ने उपस्थित सभी लोगों का मन मोह लिया।

आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्यायः सुभाष मिश्र

÷Uø संवाददाता ■ नईगढ़ी

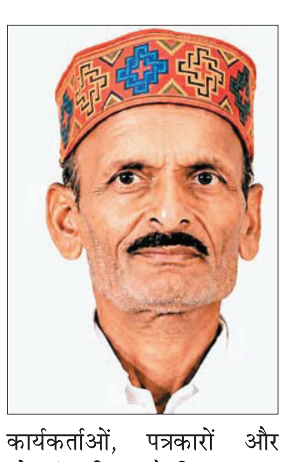

नईगढ़ी क्षेत्र के वरिष्ठ समाजसेवी सुभाष मिश्र ने 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान देश के संविधान की मूल भावना, लोकतांत्रिक संस्थाओं और नागरिक अधिकारों पर अभूतपूर्व प्रहार किया गया था। श्री मिश्र ने कहा कि 25 जून 1975 को लगाया गया आपातकाल केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, बल्कि यह देश के लोकतांत्रिक मूल्यों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों के दमन का प्रतीक बन गया। उस दौर में विपक्षी नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाने वाले हजारों लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया था। श्री मिश्रा ने कहा आपातकाल भारतीय लोकतंत्र पर लगाया गया ऐसा ग्रहण था, जिसने संविधान और लोकतांत्रिक परंपराओं को गहरी चोट पहुंचाई। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचला गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई और जनता की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। श्री मिश्र ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को आपातकाल के इतिहास से अवगत कराना आवश्यक है, ताकि वे लोकतंत्र, संविधान और नागरिक स्वतंत्रताओं के महत्व को समझ सकें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता से बड़ा संविधान और जनता का अधिकार होता है। उन्होंने उन सभी लोकतंत्र सेनानियों को नमन किया जिन्होंने आपातकाल के दौरान संघर्ष किया, जेल यातनाएं सहीं और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपना योगदान दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का त्याग और बलिदान देश के लोकतांत्रिक इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा।

कलेक्टर-कमिश्नर कांफ्रेंस से पूर्व डीपीसी ने जनशिक्षकों की ली क्लास

÷Uø संवाददाता ■ रीवा

गुरुवार 25 जून को आयोजित कमिश्नर-कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के दृष्टिगत बुधवार को डीपीसी कार्यालय रीवा में समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में डीपीसी राजेश तिवारी ने विभागीय योजनाओं एवं संबंधित कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने गुरुवार को प्रातः 11 बजे से पूर्व अपेक्षित कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण करने के स्पष्ट निर्देश दिए।समीक्षा बैठक में डीपीसी राजेश तिवारी, श्रीमती सुधा पटेल,श्रीमती दिव्या झा,दीपेंद्र सिंह बीआरसी रीवा,बुद्धि प्रकाश त्रिपाठी, नवनीत चौबे बीएसी रीवा तथा विकासखंड रीवा के जनशिक्षा केन्द्रों के जनशिक्षक उपस्थित रहे।

तय की गई अनिवार्यता

डीपीसी रीवा के निर्देशानुसार कक्षा एक की मैपिंग,कक्षा 1 से कक्षा 8 की ओवरऑल मैपिंग,कक्षा उन्नति,चाइल्ड प्रोफाइल फाइनलाइजेशन,आंगनबाड़ी ट्रॉथिंग समस्त विद्यालयों की पूर्ण की जाए एवं समान नागरिक संहिता फॉर्म का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण होना चाहिए। डीपीसी ने जनशिक्षकों की क्लास लेते हुए निर्देशित किया कि चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप द्वारा सर्व तीनों ऑप्शन शत- प्रतिशत प्रत्येक शनिवार को मेगा अपार आईडी दिवस के तहत विशेष कैंप लगाकर 100 प्रतिशतअपार आईडी जनरेट किया जाए। विद्यालय में साफ सफाई हो, शौचालय साफ सुथरा हो,किसी भी स्थिति में जर्जर कक्ष के नीचे विद्यालय संचालित ना हो, यदि अन्य कक्ष नहीं है तो निकटतम विद्यालय में विद्यालय संचालित करावें।

पनप रहा आक्रोश

आदिवासी परिवारों के विस्थापन पर पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह ने उठाई आवाज

÷Uø संवाददाता ■ मऊगंज

आदिवासी ग्राम पंचायत बेलौही (विधानसभा मऊगंज) एवं ग्राम पंचायत झौर (विधानसभा देवतालाब) के सैकड़ों वर्षों से निवासरत आदिवासी परिवारों को न्यायालय के आदेश पालन में जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के तहत हटाया जा रहा है। इस कार्रवाई को लेकर क्षेत्र में चिंता और असंतोष का माहौल देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार, प्रभावित आदिवासी परिवारों का कहना है कि बरसात के मौसम में उन्हें निवास स्थल से हटाया जा रहा है, जबकि उनके पुनर्वास अथवा वैकल्पिक आवास की कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में परिवारों के सामने रहने और आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। मामला पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के संज्ञान में आने पर उन्होंने तत्काल अपर कलेक्टर से मुलाकात कर आदिवासी परिवारों को बरसात समाप्त होने तक मोहलत देने तथा उनके लिए किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रशासन को प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था किए बिना उन्हें बेघर नहीं करना चाहिए।

आवश्यकता पड़ी तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिये तैयारः बन्ना

पूर्व विधायक श्री बन्ना ने यह भी कहा कि यदि आदिवासी परिवारों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ी तो वे उनके पक्ष में न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए भी तैयार हैं। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष हरि लाल कोल, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष आशुतोष तिवारी तथा प्रभारी के.पी. सिंह भी उपस्थित रहे। पूर्व विधायक सहित कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन से मांग की है कि आदिवासी परिवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए संवेदनशीलता के साथ निर्णय लिया जाए तथा उनके पुनर्वास की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

गावों में विद्युत लाईनों को व्यवस्थित किया जाएः किसान सुब्रत

÷Uø संवाददाता ■ रीवा

भारतीय किसान यूनियन मध्यप्रदेश प्रदेश के अध्यक्ष एव राष्ट्रीय किसान समन्वय समित के सदस्य किसान सुब्रत ने मध्यप्रदेश सरकार ,जिला प्रशासन, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी एव समस्त निर्वाचित जन प्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि ग्रामीण अंचलों में बिजली की निर्विघ्न उपलब्ध सुनिश्चित की जाय, किसानों को धान की नर्सरी तैयार करनी है पानी की आवश्यकता है निर्विघ्न विद्युत प्रदाय की जाय। मानसून के सक्रिय होने से पहले विद्युत लाईनो ,पोल गाड़ने ,केबिल लगाने ,ओव्हर लोड ट्रांसफार्मरो को बदलने एव ट्रांसफार्मरो का रख रखाव ट्रांसफार्मरों के आस पास झाडियो का नियत्रंण टांसफार्मरो के पास जल भारव ना हो अनिवार्य रूप से निरीक्षण करा सुनिश्चित किया जाय । किसान सुब्रत ने माग की है कि निर्देशित किया जाय कि समस्त विद्युत वितरण केंद्रो के अन्तर्गत आने वाले गावों मे बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी विद्युत लाईनो, पोल ,केबिल ट्रांसफार्मर सभी का निरीक्षण कर आवश्यक सुधार किया जाए।

15 खम्भों से चोरों ने काट लिए थे तार, आज तक नहीं लगे

किसान सुब्रत ने बताया कि किसानो से मिली जानकारी के अनुसार गुढ विधान सभा क्षेत्र के खैरा गांव पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण में फरवरी माह मे ग्यारह हजार लाईन के लगभग पन्द्रह खम्भो से तार किसी ने काट लिये थे,लगातार किसानो ने तार लगाने के लिए सक्षम अधिकारियो को आवेदन दिये लेकिन आज तक तार नही लगे,किसानो की खेती पहले भी प्रभावित हुई अब विद्युत आपूर्ति न होने से धान की नर्सरी प्रभावित हो रही है।

संपादकीय

उद्धव से भारी ममता की लाचारी

ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क है। ममता बनर्जी ने जो भी राजनीतिक हैसियत हासिल की, अपनी बदौलत की। उद्धव ठाकरे को तो विरासत में मिली राजनीतिक जमीन संभालनी थी। उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी तो माना जा रहा था कि राजनीतिक दांव-पेच में कमजोर होने की कीमत चुकानी पड़ी। तब शरद पवार का भी एक बयान आया था, जिसमें वो उद्धव ठाकरे को अलर्ट करने की बात कर रहे थे। शरद पवार की बातों से लगा जैसे उद्धव ठाकरे उनकी बात मान लिए होते तो अपनी पार्टी को बचा सकते थे। उन्होंने शिवसैनिकों पर अपने भरोसे के आगे शरद पवार की बातों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन ये सारी बातें तब पीछे छूट गईं, जब शरद पवार की पार्टी के साथ भी बिल्कुल वैसा हो गया, जैसा उद्धव ठाकरे के साथ हुआ था। और, अब ममता बनर्जी की पार्टी के साथ भी ठीक वैसा ही हो गया है, जैसा उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ हो चुका है। उद्धव ठाकरे को थोड़ी देर के लिए अलग रखकर देखें, तो शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज माने जाते हैं, और ममता बनर्जी खुद को पश्चिम बंगाल की स्ट्रीट फाइटर बताती रही हैं। लेकिन, सब कुछ अलग-अलग होने के बावजूद तीनों ही राजनीति में एक ही तरीके से गच्चा क्यों खा गए? जिस दिन उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करने वाले उनके सांसद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ प्रेस कांफ्रेंस कर रहे थे, उसी दिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी के बागियों ने संगठन में समानांतर व्यवस्था बनाते हुए एक झटके में ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को बेदखल कर दिया। ममता बनर्जी तो बड़ी ही अनुभवी पॉलिटिशियन हैं, ऐसा क्यों लगता है जैसे वो उद्धव ठाकरे से भी ज्यादा कमजोर पड़ गईं? कोलकाता में न्यूटाउन के एक होटल में बागी नेताओं की तरफ से तृणमूल कांग्रेस का स्पेशल सेशन बुलाया गया था। करीब आधे घंटे के विशेष अधिवेशन में पश्चिम बंगाल के बागी विधायक, पूर्व पार्षद और पदाधिकारी शामिल हुए। आयोजन के जरिए हर तरह से संदेश देने की कोशिश लग रही थी। तृणमूल कांग्रेस का चुनाव निशान प्रमुखता से दिखाया जा रहा था। मंच पर महात्मा गांधी, रवींद्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम और बीआर आंबेडकर की तस्वीरें लगी थीं परंतु ध्यान देने वाली बात यह रही कि ममता बनर्जी की कहीं कोई तस्वीर नजर नहीं आई। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 80 विधायकों में से 58 के समर्थन से ऋतब्रत बनर्जी विधानसभा में विपक्ष के नेता बनाए गए हैं। टीएमसी के 14 विधायकों ने ममता बनर्जी के प्रति अपना समर्थन जताया है, जबकि एक विधायक जेल में हैं। 28 में से 20 सांसदों ने काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया था, और वे एनसीपीआई में शामिल हो गए थे। महुआ मोइत्रा, सौगत रॉय और बाबुल सुप्रियो जैसे सांसद जरूर फील्ड में ममता बनर्जी का बचाव कर रहे हैं, लेकिन खुद ममता बनर्जी खामोश बनी हुई हैं। उनकी मुश्किलों का दायरा बहुत बड़ा हो गया है। टीएमसी के कई बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। यह पार्टी के कोषाध्यक्ष के कहने पर हुआ है। कोलकाता के एक बैंक ने टीएमसी के तीन खातों को डेबिट फ्रीज कर दिया है, और रिपोर्ट के मुताबिक, खातों में करीब 440 करोड़ रुपये जमा हैं। उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टियों के साथ जो हुआ, और लड़ाई से जो नतीजा निकला, ममता बनर्जी को निराश करने वाला है। ममता बनर्जी अब जनता की ही अदालत से उम्मीद कर सकती हैं।

लखनऊ के अलीगंज व्यावसायिक भवन में लगी भीषण आग

लापरवाही की लपटों में जलती जिंदगी: कब जागेगा तंत्र?

ललित गर्ग

लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार हैं

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में एक व्यावसायिक भवन में लगी भीषण आग ने केवल एक इमारत को नहीं जलाया, बल्कि शासन-प्रशासन की संवेदनहीनता, नियामक संस्थाओं की निष्क्रियता और व्यवस्था की खोखली पड़ चुकी जवाबदेही को भी उजागर कर दिया है। इस दुर्घटना में कोचिंग सेंटर के अनेक विद्यार्थियों की असामयिक मृत्यु ने पूरे देश को झकझोर दिया है। यह केवल एक हादसा नहीं, बल्कि उस सड़ी-गली व्यवस्था का परिणाम है, जो हर त्रासदी के बाद कुछ दिनों तक सक्रिय दिखती है और फिर गहरी नींद में सो जाती है। राजकोट के गेमिंग जोन में आग, दिल्ली के शिशु अस्पताल में नवजातों की मौत, दिल्ली के होटल अग्निकांड, मुजफ्फरपुर अस्पताल की दुर्घटना और अब लखनऊ का अग्निकांड-इन घटनाओं की श्रृंखला बताती है कि भारत में मानव जीवन का मूल्य लगातार घटता जा रहा है। हर बार वही बयान सुनाई देता है-'दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा', 'जांच के आदेश दे दिए गए हैं', 'कड़ी कार्रवाई होगी'। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या जांच और मुआवजा ही शासन का अंतिम दायित्व है? क्या सरकारें केवल दुर्घटना के बाद शोक व्यक्त करने और मुआवजा बांटने के लिए हैं? इन जहरीली काली आग ने कितने ही परिवारों के घर के चिराग बुझा दिए। कितनी ही आंखों की रोशनी छीन ली और एक कालिख पोत दी कानून और व्यवस्था के कर्णधारों के मुँह पर।

लखनऊ की जिस इमारत में आग लगी, वहां कोचिंग सेंटर और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही थीं। यह अत्यंत गंभीर प्रश्न है कि क्या उस भवन को अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त था? क्या भवन निर्माण मानकों का पालन किया गया था? क्या वहां आपातकालीन निकास मार्ग उपलब्ध थे? यदि थे, तो वे उपयोग में क्यों नहीं आए? और यदि नहीं थे, तो इतने लंबे समय तक प्रशासन की नजर इस पर क्यों नहीं पड़ी? यह केवल भवन स्वामी की लापरवाही नहीं है। यदि कोई व्यावसायिक संस्थान नियमों की अनदेखी करते हुए वर्षों तक संचालित होता रहता है, तो स्पष्ट है कि कहीं न कहीं प्रशासनिक तंत्र की मौन सहमति या भ्रष्ट गठजोड़ सक्रिय है। आखिर नगर निगम, विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी क्या है? क्या उनका कार्य केवल लाइसेंस जारी करना और औपचारिक निरीक्षण करना भर रह गया है? या कमियों को ढंकते हुए अपनी जैबें गर्म करते रहना है?

वास्तविकता यह है कि देश के अधिकांश शहरों में सार्वजनिक सुरक्षा भगवान भरोसे है। ऊंची-ऊंची इमारतें खड़ी हो रही हैं, लेकिन उनमें सुरक्षा मानकों की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। बहुमंजिला भवनों में अक्सर एक ही प्रवेश एवं निकास मार्ग होता है। अग्निशमन उपकरण या तो अनुपस्थित होते हैं या वर्षों से निष्क्रिय पड़े रहते हैं। आपदा प्रबंधन की कोई नियमित मॉक ड्रिल नहीं होती। भवनों में क्षमता से अधिक लोगों को प्रवेश दिया जाता है। नियम पुस्तकों में सुरक्षा व्यवस्था भले मौजूद हो, लेकिन जमीन पर उसकी स्थिति नगण्य है। इस विडम्बना का सबसे दुखद पक्ष यह है कि हर बड़ी दुर्घटना के बाद जांच समितियां गठित होती हैं, रिपोर्टें तैयार होती हैं, लेकिन उन रिपोर्टों पर अमल नहीं होता। उपहार सिनेमा अग्निकांड से लेकर राजकोट और लखनऊ तक, देश ने अनेक त्रासदियों से सबक लेने की बात कही, परंतु व्यवस्था ने कुछ नहीं सीखा। प्रशासन की स्मृति अत्यंत अल्पकालिक हो चुकी है। कुछ दिनों तक छापेमारी, निरीक्षण और नोटिस जारी करने का नाटक चलता है और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है।

यह स्थिति केवल प्रशासनिक अक्षमता की नहीं, बल्कि नैतिक पतन की भी है। भ्रष्टाचार ने सुरक्षा व्यवस्था की आत्मा को खोखला कर दिया है। निरीक्षण करने वाले अधिकारी सुविधा शुल्क लेकर आंखें मूंद

लेते हैं। भवन स्वामी अधिक लाभ कमाने के लिए सुरक्षा उपायों की उपेक्षा करते हैं। परिणामस्वरूप निर्दोष नागरिक अपनी जान गंवाते हैं। प्रश्न यह भी है कि क्या हमारे शहरों का विकास मानव-केंद्रित है? हम स्मार्ट सिटी, मेट्रो सिटी और विश्वस्तरीय शहरों के निर्माण की बात करते हैं, लेकिन यदि नागरिक सुरक्षित नहीं हैं, तो ऐसे विकास का क्या अर्थ है? किसी भी सभ्य समाज की पहली पहचान उसके नागरिकों की सुरक्षा होती है। यदि एक कोचिंग संस्थान, अस्पताल, होटल या मॉल भी सुरक्षित नहीं है, तो हमें अपने विकास मॉडल पर पुनर्विचार करना होगा। आज आवश्यकता केवल दोष निर्धारण की नहीं, बल्कि व्यापक संरचनात्मक सुधारों की है। सबसे पहले देशभर में सभी व्यावसायिक भवनों, कोचिंग संस्थानों, अस्पतालों, मॉल, होटल और सार्वजनिक स्थलों का स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट कराया जाना चाहिए। जिन संस्थानों के पास अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र नहीं हैं या जो मानकों का पालन नहीं करते, उन्हें तत्काल बंद किया जाना चाहिए।

दूसरे, अग्निशमन विभाग को आधुनिक संसाधनों और पर्याप्त मानवबल से सुसज्जित करना होगा। अनेक रिपोर्टों के अनुसार देश में फायर स्टेशनों और प्रशिक्षित फायर कर्मियों की भारी कमी है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण के अनुरूप अग्निशमन सेवाओं का विस्तार अत्यंत आवश्यक है। तीसरे, प्रत्येक सार्वजनिक भवन में हर छह माह में अनिवार्य मॉक ड्रिल आयोजित की जानी चाहिए। विद्यालयों, महाविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों में आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, ताकि आपात स्थिति में लोग घबराने के बजाय संयमपूर्वक अपनी सुरक्षा कर सकें। चौथे, जवाबदेही की स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। केवल भवन स्वामी ही नहीं, बल्कि संबंधित विभागों के उन अधिकारियों पर भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने लापरवाही बरती या नियमों की अनदेखी की। जब तक अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं बनाए जाएंगे, तब तक सुधार की उम्मीद करना व्यर्थ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शासन की प्राथमिकता 'दुर्घटना के बाद की प्रतिक्रिया' से बदलकर 'दुर्घटना से पूर्व की रोकथाम' पर केंद्रित होनी चाहिए। सुशासन का अर्थ केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन की रक्षा सुनिश्चित करना भी है। प्रशासन की सफलता मुआवजा राशि में नहीं, बल्कि दुर्घटनाओं को रोकने की क्षमता में निहित होती है।

कोचिंग सेंटर, हॉस्पिटल, कारखाने, होटल आदि के मिस मैनेजमेंट और लापरवाही का स्थानीय प्रशासन को अंदाजा होना चाहिए कि उसके कार्यक्षेत्र में किस तरह के व्यवसाय कानूनी प्रक्रियाओं की अनदेखी करते हुए चलाए जा रहे हैं? प्रश्न है कि इन बढ़ती दुर्घटनाओं की नृशंस चुनौतियों का क्या अंत है? बहुत कठिन है दुर्घटनाओं की उफनती नदी में जीवनरूपी नौका को सही दिशा में ले चलना और मुकाम तक पहुंचाना, यह चुनौती सरकार के सम्मुख तो है ही, आम जनता भी इससे बच नहीं सकती। मनुष्य अपने स्वार्थ और रुपए के लिए इस सीमा तक बेईमान और बदमाश हो जाता है कि हजारों के जीवन और सुरक्षा से खेलता है। दो-चार परिवारों की सुख समृद्धि के लिए अनेक घर-परिवार उजाड़ देता है। तंत्र की काहिली और आपराधिक लापरवाही के चलत ऐसे हादसे होते हैं जिनमें भ्रष्टाचार पसरा होता है, जब अफसरशाह लापरवाही करते हैं, जब स्वार्थ एवं धनलोलुपता में मूल्य बौने हो जाते हैं और नियमों और कायदे-कानूनों का उल्लंघन होता है। आखिर क्या वजह है कि जहां दुर्घटनाओं की ज्यादा संभावनाएं होती हैं, वही सारी व्यवस्थाएं फेल दिखाई देती है? सारे कानून कायदों का वहीं पर स्याह हनन होता है।

जैसे-जैसे जीवन तेज़ होता जा रहा है, सुरक्षा उतनी ही कम हो रही है, जैसे-जैसे प्रशासनिक सर्तकता की बात सुनाई देती है, वैसे-वैसे प्रशासनिक कोताही के सबूत सामने आते हैं, मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन हर बड़ी दुर्घटना कुछ शोर-शराबें के बाद एक और नई दुर्घटना की बाट जोहने लगती है। सरकार और सरकारी विभाग जितनी तत्परता मुआवजा देने में और जांच समिति बनाने में दिखाते हैं, अगर सुरक्षा प्रबंधों में इतनी तत्परता दिखाएं तो दुर्घटनाओं की संख्या घट सकती है। लखनऊ का यह अग्निकांड एक चेतावनी है। यदि अब भी शासन-प्रशासन नहीं जागा, तो ऐसी त्रासदियां भविष्य में और अधिक भयावह रूप धारण कर सकती हैं। यह समय आत्ममंथन का है, क्योंकि हर अग्निकांड के बाद यदि केवल राख बचती है और व्यवस्था फिर उसी ढर्रे पर लौट जाती है, तो यह केवल लापरवाही नहीं, बल्कि एक प्रकार का संस्थागत अपराध है। देश को अब संवेदना नहीं-व्यवस्था चाहिए, जांच नहीं-जवाबदेही चाहिए और आश्वासन नहीं-ठोस कार्रवाई चाहिए। अन्यथा हर अग्निकांड के बाद यही प्रश्न गूंजता रहेगा-आखिर कब जागेगा तंत्र?

तनाव के बीच उम्मीद

आदित्य नारायण चौपड़ा

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं

अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के अंतिम परिणाम को लेकर अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है। स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच हुई पहले दौर की बातचीत में भी तनातनी बनी रही। अमेरिका प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जे.डी.वेंस, विशेषदूत स्टीव विटकॉफ और वरिष्ठ सलाहकार जेरेड कुशनर ने किया। जबकि ईरान की तरफ से प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री अब्बास अराघची और संसदीय अध्यक्ष मोहम्मद गालिबाफ ने किया। यद्यपि 80 मिनट की वार्ता के बाद ईरान प्रतिनिधिमंडल बैठक से बाहर आ गया और उसने शांति समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया। तनाव के बावजूद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प व्यापक क्षेत्रीय युद्ध विराम हासिल करने के लिए तेहरान के साथ राजनयिक संबंध फिर से शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जेडी वेंस ने वार्ता को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि हमारे सामने सवाल यह है कि हम मिलकर और कितना कुछ हासिल कर सकते हैं क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं क्या हम मध्य पूर्व में संबंधों को स्थायी रूप से बदल सकते हैं या फिर हम पुराने तरीके पर लौट जाएंगे, जो हमारी पसंद नहीं है लेकिन निश्चित रूप से ऐसा होने की पूरी संभावना है।

वेंस ने कहा कि ट्रम्प ने अमेरिकी टीम को ईरान के साथ संबंधों में मौलिक बदलाव लाने का निर्देश दिया था, यदि तेहरान उन गतिविधियों को छोड़ने की इच्छा दिखाता है जिन्हें वाशिंगटन अस्थिरता पैदा करने वाला मानता है। वेंस ने कहा, राष्ट्रपति ट्रम्प ने हमसे जो करने को कहा है, वह ईरान के लोगों के साथ हमारे संबंधों को बदलने के लिए एक नई शुरुआत करना है। यदि ईरान का नेतृत्व क्षेत्रीय अस्थिरता का कारक बनने से पीछे हटने को तैयार है, यदि वे दीर्घकालिक रूप से परमाणु हथियार बनाने की महत्वाकांक्षाओं को छोड़ने को तैयार हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका उस देश के साथ अपने संबंधों को मौलिक रूप से बदलने को तैयार है।

लेकिन असली मुद्दा लेबनान में इजराइली हमलों का रहा। यद्यपि डोनाल्ड ट्रम्प ने इजराइल को कड़ी फटकार लगाते हुए उन्हें लेबनान और हिजबुल्लाह के मामले में जिम्मेदारी दिखाने को कहा है। इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाता जा रहा है। जिसकी वजह से रोज लोग मर रहे हैं लेकिन नेतन्याहू शांति समझौते के विरुद्ध सख्त रवैया अपनाए हुए है। ईरान कई सालों से हिजबुल्लाह का पालन पोषण कर रहा है और इजराइल के विरुद्ध प्रोक्सी युद्ध में उसका इस्तेमाल कर रहा है। यद्यपि जेडी वेंस सुलह का रुख अपनाए हुए हैं लेकिन ट्रम्प वार्ता के दौरान भी तेहरान को कड़ी चेतावनियां देने से बाज नहीं आ रहे।

ट्रम्प दबाव की रणनीति अपना रहे हैं और लगातार धमकी दे रहे हैं कि अगर ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह की गतिविधियों पर लगाम नहीं लगाई तो फिर अमेरिका ईरान पर बहुत बड़ा प्रहार करेगा। इसी बीच ट्रम्प ने एक नया राग छेड़ दिया है। ट्रम्प लेबनान और हिजबुल्लाह से जुड़े मामलों में सीरिया को जिम्मेदारी सौंपने की बात कह रहे हैं। ट्रम्प का मानना है कि सीरियाई सरकार लेबनान में ईरान समर्थित आतंकी समूह हिजबुल्लाह की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ी भूमिका निभा सकता है जबकि सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल लेबनान के मामलों में अपने हाथ नहीं जलाना चाहते। उनका कहना है कि वे लेबनान में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे लेकिन वे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए प्रयासों का समर्थन करते हैं।

सवाल यह भी है कि क्या इजराइल सीरिया की भूमिका को स्वीकार करेगा। स्विट्जरलैंड में टकराव के बावजूद बातचीत की निगरानी के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन भी किया गया। दोनों पक्षों ने लेबनान में सैन्य अभियानों को समाप्त करने के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य पर एक संचार लाइन और एक संघर्ष निवारण सैल की स्थापना की। इसी बीच अमेरिका ने ईरानी तेल निर्यात पर लगे कुछ प्रतिबंधों को हटा दिया है और कुछ जब्त सम्पतियों को भी जारी कर दिया है। बातचीत में मध्यस्थ कतर का कहना है कि वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है क्योंकि दोनों पक्षों ने 60 दिवसीय रोड मैप पर सहमति जताई है। जेडी वेंस शांति समझौते को लेकर सकारात्मक रुख इसलिए अपनाए हुए हैं क्योंकि उनका राजनीतिक भविष्य इसी समझौते पर टिका हुआ है।

जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के चुनावों में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रम्प के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रम्प इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। अमेरिका में भी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। जेडी वेंस के लिए शांति समझौता उनके राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। हालांकि मार्को रूबियो भी राष्ट्रपति पद के लिए संभावित दावेदार हैं लेकिन ज्यादातर सर्वेक्षणों में वेंस को बढ़त दिखाई दे रही है। अमेरिका और खाड़ी देश जल्द से जल्द होर्मुज को खुलवाना चाहते हैं क्योंकि ऐसा न होने की स्थिति में तेल और ऊर्जा का संकट बढ़ जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात तो होर्मुज पर निर्भरता कम करने की रणनीति पर काम कर रहा है। भारत के लिए भी होर्मुज संकट एक बड़ा सबक है। भारत के लिए आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाना वैकल्पिक समुद्री एवं जमीनी गलियारों में निवेश करना और रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत बनाना प्राथमिकता होनी चाहिए। तनातनी में खत्म हुई शांति वार्ता में प्रगति तो हुई है लेकिन रास्ते अभी भी जटिल हैं। बेहतर यही होगा कि अमेरिका-ईरान संयम से काम लेते हुए नई शुरूआत करें और पूरी दुनिया को राहत प्रदान करें।

किस्मत नहीं, आपकी आदतें तय करती हैं कि आप अमीर बनेंगे या नहीं!

हर कोई अमीर बनने के सपने देखता है, लेकिन जीवन में कुछ लोग ही ये सपना पूरा कर पाते हैं। कुछ लोग आम परिवारों में पैदा होकर भी बहुत अमीर बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग रात-दिन मेहनत करके भी पैसों की तंगी से बाहर नहीं निकल पाते हैं लेकिन क्या अमीर बनना सिर्फ किस्मत का खेल है? या फिर उनके पास कोई ऐसा सीक्रेट होता है? आचार्य चाणक्य का मानना था कि पैसा और कामयाबी कभी अचानक या इत्तेफाक से नहीं मिलते। इसके पीछे कुछ खास नियम, आदतें और सही फैसले होते हैं, जो एक आम इंसान को भी बहुत बड़ा बना सकते हैं।

सीखना न छोड़ें

चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान एक ऐसी दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। आज के समय में सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं, बल्कि आपका नॉलेज और हुनर है। आप जितना नया सीखेंगे, आपकी वैल्यू उतनी ही बढ़ेगी और आप जीवन में उतने ही बेहतर फैसले ले पाएंगे।

वक्त की कद्र करें

चाणक्य का मानना है कि जो इंसान समय को बर्बाद करता है, समय एक दिन उसे बर्बाद कर देता है। हर इंसान के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन आप सफल होंगे या नहीं, यह इस बात पर तय होता है कि आप इन घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं।

सही मौके को पहचानें

चाणक्य नीति कहती है कि समझदार इंसान अच्छे मौके का इंतजार नहीं करता, बल्कि सामने आते ही उसे पहचानकर उसका फायदा उठाता है। जीवन में कामयाबी और नाकामी के बीच का अंतर सिर्फ आपकी मेहनत नहीं, बल्कि सही समय पर लिया गया सही फैसला होता है। मौके हर किसी को मिलते हैं, बस कुछ लोग डर या आलस की वजह से उन्हें खो देते हैं, तो कुछ लोग उनका फायदा उठा लेते हैं।

पैसों का सही इस्तेमाल करें

चाणक्य के अनुसार, जो इंसान पैसों का सही इस्तेमाल करना नहीं जानता, उसके पास धन कभी नहीं रुकता। पैसा कमाना एक हुनर है, लेकिन उसे संभालना और बढ़ाना उससे भी बड़ा हुनर है। ज्यादातर लोग कमाते तो बहुत हैं, लेकिन बचत और सही जगह पैसा न लगाने की वजह से कभी अमीर नहीं बन पाते।

अच्छे लोगों के साथ रहें

चाणक्य नीति कहती है कि इंसान जैसा साथ रखता है, वैसा ही बन जाता है। आप जिन लोगों के साथ उठते-बैठते हैं, उनकी सोच और आदतें धीरे-धीरे आप में भी आने लगती हैं। इसलिए, अच्छे और कामयाब लोगों की संगति आपको आगे ले जाएगी, जबकि गलत लोगों का साथ आपको पीछे धकेल देगा।

डॉ. आशीष वशिष्ठ

अपना बोया ही काट रहीं ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस को मिली ऐतिहासिक पराजय के बाद, जिस तरह पार्टी के विधायक और सांसद ममता बनर्जी से नाता तोड़ रहे हैं, उसने कई लोगों को हैरान किया है। लेकिन ममता बनर्जी पिछले 28-29 सालों से जिस तरह की सिद्धान्तहीन राजनीति करती रही हैं, उसे देखते हुए इन जन-प्रतिनिधियों के कारनामे कुछ भी असामान्य नहीं लगते। वे बस वही कर रहे हैं जो ममता दीदी ने उन्हें सिखाया है। असल में, अच्छा शिष्य वही है जो अपने गुरु के दिखाए रास्ते पर चले। ये सांसद और विधायक भी वही कर रहे हैं जो ममता बनर्जी करती रही हैं, यानी बिना किसी सिद्धांत या आदर्शवादी राजनीति। किसी को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना और काम निकल जाने पर उसे छोड़ देना, बार-बार उससे मुंह मोड़ लेना और विपक्षी पार्टियों के विधायकों पर हमला करना।

तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों और सांसदों पर मुख्य आरोप यह है कि तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद, वे अब विपक्षी भाजपा के साथ मिल रहे हैं, वही भाजपा, जिसे उन्होंने चुनाव के दौरान सांप्रदायिक पार्टी बताकर हराया था। लेकिन ममता बनर्जी ने भी 1998 में ऐसा ही किया था, जब उन्होंने 1 जनवरी 1998 को कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस का गठन किया था। उस समय ममता बनर्जी को कांग्रेस से यह शिकायत थी कि राज्य में लेफ्ट फ्रंट को हराने के लिए कांग्रेस भाजपा के साथ हाथ क्यों नहीं मिला रही है? उस समय ममता भाजपा को सांप्रदायिक नहीं मानती थीं। उन्होंने यह भी कहा था कि भाजपा कोई सांप्रदायिक पार्टी नहीं है। तो, अगर अब तृणमूल कांग्रेस के सांसद और विधायक कह रहे हैं कि भाजपा सांप्रदायिक पार्टी नहीं है, तो इसमें क्या गलत है? वे बस अपनी प्रिय नेता के पदचिन्हों पर चल रहे हैं।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चार बार (2013, 2017, 2022 और 2024 में) अपना पक्ष बदला, लेकिन ममता बनर्जी अब तक पांच बार अपना पक्ष बदल चुकी हैं। इतिहास के पन्ने पलटे तो, बात 1997 की है, केंद्र में संयुक्त मोर्चा की सरकार थी। संयुक्त मोर्चा सरकार को बाहर से समर्थन दे रही कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया, नतीजतन नवंबर 1997 में सरकार गिर गई और 1998 में नए सिरे से लोकसभा चुनाव हुए। तब तक ममता कांग्रेस छोड़कर एक नई पार्टी बना चुकी थीं। चुनावों में ममता की तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा के साथ सीट का समझौता किया और सात सीटें जीतीं। हालांकि, वह सरकार में शामिल नहीं हुईं क्योंकि उन्होंने राज्य में अपनी नई बनी पार्टी को मजबूत करने पर ध्यान दिया। 13 महीने बाद केंद्र सरकार गिर गई।

1999 के चुनावों के बाद एक नई सरकार बनी, जिसमें ममता बनर्जी रेल मंत्री बनीं। 2001 में, जब बंगाल विधानसभा चुनाव नजदीक थे, तो ममता को लगा कि कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करना फायदेमंद रहेगा। इसलिए, मार्च 2001 में उन्होंने रक्षा क्षेत्र में भ्रष्टाचार के मामले (तहलका स्टिंग ऑपरेशन) का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। हालांकि, इससे भी बंगाल में लेफ्ट फ्रंट को हराया नहीं जा सका। लेफ्ट फ्रंट ने 199 सीटें जीतीं, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 31 प्रतिशत वोट के साथ सिर्फ 60 सीटें मिलीं।

अगले विधानसभा चुनाव में अभी पांच साल बाकी थे और केंद्र में भाजपा की सरकार थी। इसलिए, 2003 में ममता बनर्जी फिर से वाजपेयी सरकार में शामिल हो गईं। वह सितंबर 2003 में वाजपेयी सरकार में मंत्री बनीं, जबकि गुजरात दंगे डेढ़ साल पहले, यानी फरवरी 2002 में हो चुके थे। उन्होंने दंगों के लिए गुजरात में मोदी सरकार के इस्तीफे की मांग की थी, लेकिन जब अप्रैल 2002 में लोकसभा में वाजपेयी सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया, तो ममता की पार्टी ने वाजपेयी का समर्थन किया। इस समर्थन के बदले, कुछ महीनों बाद उन्हें फिर से मंत्री बनाया गया।

ममता बनर्जी ने 2004 के लोकसभा और 2006 के विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ गठबंधन करके लड़े। हालांकि, जब उनकी पार्टी को दोनों चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा। 2004 के लोकसभा चुनावों में तृणमूल को सिर्फ एक सीट मिली और 2006 के विधानसभा चुनावों में न सिर्फ पार्टी का वोट शेयर घटा (26 प्रतिशत हो गया) बल्कि उसकी सीटें भी आधी रह गईं, तो ममता को लगा कि भाजपा के साथ गठबंधन करने का कोई फायदा नहीं है। केंद्र में भाजपा के सत्ता से बाहर होने के बाद, ममता बनर्जी ने फिर से कांग्रेस पार्टी का रुख किया। उन्होंने 2009 के लोकसभा चुनाव मिलकर लड़े। तृणमूल कांग्रेस ने 19 सीटें जीतीं। इस जीत से उत्साहित होकर, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर 2011 का विधानसभा चुनाव लड़ा और सरकार बनाई।

सरकार बनाने के ठीक एक साल बाद, ममता ने कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दिया, क्योंकि उन्हें अब कांग्रेस की सीढ़ी की जरूरत नहीं थी, लेकिन वह यहीं नहीं रुकीं। वह उस सीढ़ी को ही आग लगाने पर आमादा थीं। इसलिए उन्होंने विपक्षी विधायकों को एक-एक करके तोड़ना शुरू किया और अगले पांच सालों में कांग्रेस पार्टी के 42 विधायकों को अपनी तरफ कर लिया। कांग्रेस ही पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस बन चुकी थी। उन्होंने लेफ्ट फ्रंट के चार विधायकों को भी पार्टी में शामिल किया, जबकि उन्हें उनकी जरूरत नहीं थी। इन विधायकों के बिना भी, पार्टी के पास 184 विधायकों का मजबूत बहुमत था।

2016 के विधानसभा चुनाव के बाद भी ममता बनर्जी ने विपक्षी विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करना जारी रखा, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने पहली बार अकेले चुनाव लड़ा था और 211 सीटें जीती थीं। उन्हें विपक्षी विधायकों को अपने पाले में लाने की जरूरत नहीं थी। फिर भी, अगले पांच सालों में उन्होंने कांग्रेस के 18 और लेफ्ट फ्रंट के 4 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। यह सिलसिला 2021 के चुनावों के बाद भी जारी रहा, जब भाजपा के टिकट पर चुने गए 7 विधायक तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। इनमें से सिर्फ तीन या चार विधायकों ने अपनी सीट से इस्तीफा दिया और तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर उपचुनाव लड़ा। बाकी नेता अपनी सीटें छोड़े बिना तृणमूल कांग्रेस के साथ बने रहे। स्पीकर उनकी सदस्यता रद्द करने की याचिकाओं पर कोई फैसला नहीं ले रहे थे, जबकि वे अपना विधायी कार्यकाल पूरा करते रहे। कुछ नेता तो मंत्री भी बन गए, और कुछ ने सत्ता के फायदों का आनंद लेना जारी रखा।

विपक्ष के जिन विधायकों ने मंत्री पद, पैसे और सत्ता के लिए पाला बदला था, और ममता बनर्जी को उसमें कुछ भी अनैतिक नहीं लगा था, वही काम आज उनकी 'अपनी' पार्टी के तृणमूल विधायक और सांसद भी कर रहे हैं; तो फिर ममता को क्या शिकायत होनी चाहिए? बागी तृणमूल विधायक और सांसद अपना नया गुट बनाकर भाजपा नीत एनडीए के पक्ष में खड़े है। असल में आज ममता दीदी को वही फसल काटनी पड़ रही है, जो खुद उन्होंने बोयी थी। तृणमूल कांग्रेस के पंद्रह साल के कार्यकाल में जो अत्याचार, अनाचार और भ्रष्टाचार हुआ है, उससे ममता दीदी की छवि को गहरा धक्का लगा। आज उनके साथ जो हो रहा है, वो उनके कर्मों का ही नतीजा है। इसलिए उनके साथ न उनके नेता खड़े हैं, और न ही जनता। तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के साथ आज जो कुछ हो रहा है, उस घटनाक्रम से ममता बनर्जी के सिवाय कोई दूसरा दुखी भी नहीं है।

दो दिन में लोकेशन फाइनल करने के निगमायुक्त ने दिए आदेश

53 अर्धविकसित और 90 अविकसित पार्क होंगे विकसित, बारिश से पहले पौधरोपण की तैयारी

नगर संवाददाता ■ ग्वालियर

वर्षाकाल को ध्यान में रखते हुए सभी कार्य युद्धस्तर पर पूरे किए जाएं, ताकि शहर में हरियाली बढ़ाने की योजना प्रभावी रूप से लागू हो सके। यह निर्देश निगमायुक्त संघ प्रिय ने बुधवार को पार्क विभाग की समीक्षा बैठक लेकर शहर के पार्कों के विकास और पौधारोपण कार्यों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए। आयुक्त ने सबसे पहले आगामी पौधारोपण अभियान की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्षा ऋतु शुरू होने से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। नगर निगम क्षेत्र में ऐसे स्थान चिन्हित किए जाएं, जहां बड़े स्तर पर जनभागीदारी के साथ पौधारोपण किया जा सके। इसके लिए दो दिनों के भीतर उपयुक्त स्थानों की सूची तैयार कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में पार्कों की स्थिति की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने 53 अर्धविकसित और 90 अविकसित पार्कों को विकसित करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि इन पार्कों को प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जाए ताकि शहर में हरियाली और सार्वजनिक उपयोग की सुविधाएं बढ़ सकें। बैठक में अपर आयुक्त प्रदीप तोमर, सहायक यंत्री अजय शाक्यवार, पार्क अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान सहित पार्क पर्यवेक्षक उपस्थित रहे।

पार्क गोद लेने की प्रक्रिया में तेजी

आयुक्त ने पार्क गोद देने की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जिन दानदाताओं या संस्थाओं ने पार्क गोद लिए हैं, उन्हें औपचारिक रूप से हस्तांतरित किया जाएं ताकि उनके माध्यम से पार्कों का बेहतर रखरखाव और विकास सुनिश्चित हो सके। समीक्षा के दौरान आयुक्त ने सभी पार्कों में स्थापित फाउंटेन को नियमित रूप से चालू रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पार्कों में आने वाले नागरिकों को स्वच्छ, सुंदर और सुविधाजनक वातावरण मिलना चाहिए, यह नगर निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

स्ट्रीट लाइट व्यवस्था होगी हाईटेक

निगमायुक्त संघ प्रिय ने विद्युत विभाग और स्मार्ट सिटी अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेकर शहर की विद्युत व्यवस्था और स्ट्रीट लाइट सिस्टम की विस्तृत समीक्षा की। बैठक के दौरान आयुक्त ने स्ट्रीट लाइट संधारण में उपयोग हो रही हाइड्रोलिक मशीनों की कार्यक्षमता की जानकारी ली और उनके बेहतर उपयोग पर चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिए कि हाल ही में खरीदे गए वाहनों को शीघ्र कार्य में लगाया जाए तथा सभी वाहनों के बीमा, पंजीयन और अन्य दस्तावेज अद्यतन रखे जाएं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी स्थिति में शहर की सड़कें अंधेरे में नहीं रहनी चाहिए और सभी लाइटें नियमित रूप से चालू रहनी चाहिए।

पुलिस की लापरवाही पर अदालत सख्त, फरार ननद के खिलाफ जल्द चालान पेश करने के आदेश

नगर संवाददाता ■ ग्वालियर

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती मानसी बलूजा ने एक महत्वपूर्ण आदेश में थाना हजीरा पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ा रुख अपनाते हुए पीड़िता पिंकी शर्मा के मामले में फरार चल रही मुख्य आरोपी ननद रीना शर्मा उर्फ रानू के विरुद्ध शीघ्र विवेचना पूरी कर अंतिम प्रतिवेदन (चालान) न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। पीड़िता पिंकी शर्मा की ओर से अधिवक्ता मनीष आनंद एवं अक्षिता सिंह ने न्यायालय के समक्ष यह तर्क रखा कि पुलिस ने मामले में पति राहुल शर्मा और सास सरला शर्मा के खिलाफ तो चालान पेश कर दिया, लेकिन मुख्य आरोपी ननद रीना शर्मा के विरुद्ध न तो गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई और न ही चालान पेश किया गया। मामला अपराध क्रमांक 350/2024 से संबंधित है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत पति, सास और ननद के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था। पीड़िता की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपी रीना शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका सितंबर 2024 में निरस्त हो चुकी है, इसके बावजूद वह खुलेआम घूम रही है और समझौता नहीं करने पर पीड़िता के परिजनों को तेजाब फेंकने तथा जान से मारने की धमकियां दे रही है। सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि किसी आरोपी की गिरफ्तारी न होने के आधार पर विवेचना को अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रखा जा सकता और फरार आरोपी के खिलाफ भी चालान प्रस्तुत किया जा सकता है। इस तर्क से सहमत होते हुए न्यायालय ने पुलिस की दलीलों को खारिज कर थाना प्रभारी हजीरा को आरोपी की तलाश जारी रखते हुए विवेचना पूरी करने और यथाशीघ्र अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के आदेश दिए।

महाराज बाड़ा से लेकर सराफा तक चला अतिक्रमण हटाओ अभियान

ग्वालियर। शहर के सबसे व्यस्ततम और ऐतिहासिक क्षेत्र महाराज बाड़ा, सराफा और उससे जुड़े प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए निगम के मदाखलत अमले ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की। नोडल अधिकारी केशव सिंह चौहान एवं मदाखलत अधिकारी के निर्देशन में निगम टीम ने महाराज बाड़ा क्षेत्र के बाजारों में कार्रवाई करते हुए मार्ग अवरुद्ध कर रहे हाथ ठेलों और फुटपाथियों को हटाया।

सावरकर शाखा ने वृद्धाश्रम में वितरित की खाद्य सामग्री

ग्वालियर। भारत विकास परिषद, वीर सावरकर शाखा द्वारा अपने सेवा प्रकल्प के अंतर्गत बुधवार को लक्ष्मीगंज स्थित माधव वृद्ध आश्रम में निवासरत वृद्धजनों के लिए अन्न एवं खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। यह सेवा कार्य शाखा के सदस्य डॉ. बीएम कुलश्रेष्ठ के वित्तीय सहयोग से संपन्न हुआ। इस अवसर पर उपस्थित शाखा पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने समाज के वरिष्ठ नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता एवं सेवा भावना को सर्वोपरि बताया। इस मौके पर शाखा अध्यक्ष मेजर डी राय, प्रदीप तरसोलिया, केके शर्मा, अरुण अग्रवाल, आरके गुप्ता, पुनीत अग्रवाल, संजय गुप्ता एवं नूतन श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे।

इमेज एडवरटाइजिंग पर 91.66 लाख बकाया वसूली का मामला न्यायालय पहुंचा

■ **नोटिस के बावजूद भुगतान नहीं, निगम ने पहली बार दायर किया परिवाद**

नगर संवाददाता ■ ग्वालियर

नगर निगम की विज्ञापन शाखा से जुड़े एक बड़े राजस्व मामले में फर्म मैसर्स इमेज एडवरटाइजिंग के खिलाफ अब न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया है। फर्म पर 91 लाख 66 हजार 112 रुपए की बकाया राशि न जमा करने का आरोप है, जिसे वसूलने के लिए नगर निगम ने विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट नगर निगम के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया है।

मैसर्स इमेज एडवरटाइजिंग के डायरेक्टर सुधीर हरयल (पंचशील पार्क, नई दिल्ली) ने वर्ष 2013 में नगर निगम से 10 वर्षों के लिए ग्रेंटी लगाने का टेंडर लिया था। इसके तहत वर्ष 2014 से 2024 तक अनुबंध के अनुसार कुल 2 करोड़ 59 लाख रुपए जमा किए जाने थे। निगम द्वारा 24 फरवरी 2014 को अनुबंध संपादित कर कार्यादेश जारी किया गया था।

फर्म द्वारा अब तक केवल 1 करोड़ 67 लाख 33 हजार 888 रुपए ही जमा किए गए हैं, जबकि शेष 91 लाख 66 हजार 112 रुपए अभी भी बकाया हैं।

नगर निगम द्वारा संबंधित फर्म को कई बार नोटिस जारी किए गए। इनमें 19 जनवरी 2022, 16 जनवरी 2024, 4 दिसंबर 2024, 30 जनवरी 2025, 17 फरवरी 2025 और 25 मार्च 2025 को बकाया राशि जमा करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद फर्म ने राशि जमा नहीं की। लगातार अनदेखी के बाद निगमायुक्त संघ प्रिय के आदेश पर विज्ञापन शाखा के नोडल अधिकारी अनूप लिटोरिया ने विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट नगर निगम के न्यायालय में परिवाद दायर किया है। दायर परिवाद पर न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए संबंधित फर्म के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है।

पिंटो पार्क में अवैध फिश मार्केट पर चला बुलडोजर

ग्वालियर,न.सं.। शहर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। वार्ड क्रमांक 19 के पिंटो पार्क पानी की टंकी के पास आज बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बन रही फिश मार्केट (फिश पार्लर) की निर्माणाधीन दुकानों को हटा दिया गया। निगमायुक्त संघ प्रिय के निर्देश पर जोन 8 की टीम मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण को तत्काल रुकवाकर बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की। बताया गया कि क्षेत्र में बिना अनुमति फिश मार्केट के लिए दुकानों का निर्माण किया जा रहा था। जिस पर बुधवार को अमले ने मौके से हटा दिया।

पेट्रोल नहीं देने पर बदमाश ने युवक को लगाई आग, गंभीर

नगर संवाददाता ■ ग्वालियर

शहर के थाटीपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार की देर रात पेट्रोल नहीं देने के विवाद पर बदमाशों ने एक युवक को पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की, उसे गंभीर हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वहीं उसे बचाने आए उसके पिता भी झुलस गए। पुलिस ने दो आरोपियों बाली उर्फ अनुज गुर्जर और सचिन गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है जबकि अरविन्द छावई फरार है।

न्यू प्रेम नगर, पीएसी कॉलोनी के पास रहने वाले आकाश सेंगर (26) पुत्र रामचंद्र सेंगर पर क्षेत्र के बदमाश बाली गुर्जर, सचिन और अरविन्द ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना मंगलवार रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपी किसी बात को लेकर आकाश से विवाद कर रहा था। इसी दौरान पेट्रोल देने से मना करने पर वह आगबबूला हो गया और उसने आकाश के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर उसे आग लगा दी।

आग की लपटों में घिरे बेटे को बचाने के लिए उसके पिता रामचंद्र सेंगर मौके पर पहुंचे, लेकिन इस दौरान उनके पैर भी आग की चपेट में आ गए और वे घायल हो गए। रामचंद्र सेंगर घटनास्थल के समीप स्थित एक टूर एंड ट्रेवल्स कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्यरत हैं। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल आग बुझाने का प्रयास किया और गंभीर रूप से झुलसे पिता-पुत्र को उपचार के लिए जयारोग्य अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती कराया। आकाश की स्थिति गंभीर बताई गई है। बताया गया है कि आकाश सेंगर थाटीपुर चौराहे स्थित ऑटो स्टैंड पर वाहनों को खड़ा कराने का काम करता है।

सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट घोषित 44 विद्यार्थियों को मिली सफलता

नगर संवाददाता ■ ग्वालियर

द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा बुधवार को सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट घोषित किया गया। शहर की बात करें तो इस बार शहर से कुल 298 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जिसमें से कुल 44 विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की। इस परीक्षा में कुल 74 विद्यार्थियों ने दोनों ग्रुप्स की परीक्षा एक साथ दी, जिनमें से 4 विद्यार्थियों ने दोनों ग्रुप में एक साथ सफलता प्राप्त की, वहीं 3 विद्यार्थियों का पहला एवं 2 का दूसरा ग्रुप निकला। केवल पहला ग्रुप देने वालो की संख्या 133 थी, जिसमें से 18 विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की एवं कुल 91 विद्यार्थियों ने केवल दूसरे ग्रुप की परीक्षा दी, जिसमें से 17 विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की। इस मौके पर ग्वालियर ब्रांच के पदाधिकारी चेयरपर्सन सीए निधि अग्रवाल, सचिव विवेक कुमार जैन, कोषाध्यक्ष सीए गगन जैन, सिकासा चेयरमैन सीए नगेन्द्र सिंह कुशवाह, इमिडिएट पास्ट चेयरमैन सीए मयूर गर्ग ने सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई दी हैं।

ये रहे सिटी टॉपर

- पहला स्थान पीयूष गुप्ता को मिला, इन्होंने 600 में 354 अंक प्राप्त किए।
- दूसरे स्थान पर अभिनव चांदील रहे, इन्होंने 600 में से 344 अंक प्राप्त किए।
- तीसरा स्थान राज लाडखानी को मिला, इन्होंने 600 में से 322 अंक हासिल किए।
- चौथे स्थान पर कनक शर्मा रहीं, इन्होंने 600 में 300 अंक प्राप्त किए।

इनका कहना है

पिछली बार की अपेक्षा इस बार शहर का रिजल्ट कम रहा है। स्टूडेंट्स को अब साल में तीन बार परीक्षा देने के अवसर मिल रहे हैं। ऐसे में जो विद्यार्थी इस बार सफल नहीं हुए हैं वे निराश न हों। ब्रांच द्वारा स्टूडेंट्स के लिए आयोजित मॉक टेस्ट एवं जरूरी सेमिनार को जरूर अटेंड करें। इसका फायदा परीक्षा में जरूर मिलता है। साथ ही साथ इंस्टिट्यूट का मटेरियल काफी लाभदायक रहता है उसे प्राथमिकता देना चाहिए।

सीए पंकज शर्मा, उपाध्यक्ष, ग्वालियर ब्रांच आईसीएआई

परिषद अध्यक्ष ने मुरैना में मोर अभयारण्य बनाने मुख्यमंत्री व विस अध्यक्ष को लिखा पत्र

नगर संवाददाता ■ ग्वालियर

मुरैना में मोर अभयारण्य बनाने की मांग, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को नगर निगम परिषद ग्वालियर के अध्यक्ष मनोज तोमर ने पत्र लिखा है। श्री तोमर ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर मांग की है कि मुरैना जिले में राष्ट्रीय पक्षी मोर के संरक्षण के लिए विशेष मोर अभयारण्य स्थापित किया जाए। इससे मुरैना एवं ग्वालियर जिले में पर्यटन को भी बढावा मिलेगा। पत्र में लिखा है कि मुरैना जिले में बड़ी संख्या में मोर पाए जाते हैं, लेकिन उनके संरक्षण के लिए अभी तक कोई समर्पित अभयारण्य नहीं है। आए दिन समाचारों के माध्यम से मोरों के घायल होने और उनकी मौत की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा है कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और देश में अभी तक ऐसा कोई विशिष्ट अभयारण्य नहीं है, जहां केवल मोरों के संरक्षण और संवर्धन का कार्य किया जाता हो। पत्र में उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि जिस प्रकार प्रदेश के श्योपुर जिले में चीता संरक्षण के लिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान विकसित किया गया है, उसी प्रकार नई पहल के रूप में मुरैना जिले में भी मोरों के संरक्षण के लिए एक समर्पित मोर अभयारण्य विकसित किया जाना चाहिए।

माहेश्वरी समाज के लोग उत्कृष्ट कार्य कर समाज को कर रहे गौरवान्वित : अशोक शर्मा

■ **महेश नवमी का समापन, प्रतियोगिता के विजेताओं का हुआ सम्मान**

नगर संवाददाता ■ ग्वालियर

ग्वालियर जिला माहेश्वरी सभा द्वारा आयोजित महेश नवमी सप्ताह का समापन मंगलवार को जलसा गार्डन में पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में साड़ा अध्यक्ष अशोक शर्मा एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में माहेश्वरी समाज के अतुल माहेश्वरी उपस्थित थे।

कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान महेश की पूजा-अर्चना एवं समाज की बालिकाओं आहना सोमानी, दिव्यांशी भूतड़ा एवं सौम्या माहेश्वरी द्वारा प्रस्तुत महेश वंदना के नाट्य मंचन से हुआ। मंचासीन अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान मधुसूदन माहेश्वरी, आरपी माहेश्वरी, आशुतोष माहेश्वरी, शैलेश माहेश्वरी ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि माहेश्वरी समाज अपनी समृद्ध विरासत एवं मूल्यों से कभी समझौता नहीं करता। उन्होंने कहा कि राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में माहेश्वरी समाज के लोग उत्कृष्ट कार्य कर समाज का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। उन्होंने महेश नवमी सप्ताह के दौरान समाज द्वारा किए गए 101 यूनिट रक्तदान की सराहना करते हुए इसे समाज सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। इस मौके पर अतुल माहेश्वरी ने समाज की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि समाज द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में छात्रवृत्ति योजना, विधवा महिला पेंशन योजना तथा कम ब्याज दर पर व्यवसायिक ऋण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कार्यक्रम में मेधावी छात्र-छात्राओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से नवीन डागा, रामू माहेश्वरी, विष्णु भुराड़िया, रामावतार मेंया, यतेंद्र गुप्ता, कृष्ण गोपाल लड्ढा, मनोज मालू, सुनील मालू, लता चांडक, नीता माहेश्वरी, सविता पेड़ीवाल, रश्मि मालू सहित अनेक समाजजन उपस्थित रहे।

इनका हुआ सम्मान

'हर घर महादेव' शिवलिंग प्रतियोगिता के महिला वर्ग में प्रथम पुरस्कार पुष्पा लोईवाल, द्वितीय पुरस्कार ऋचा खड़ोड़ एवं तृतीय पुरस्कार ज्योति लाखोटिया को प्रदान किया गया। वहीं बालिका वर्ग में प्रथम पुरस्कार आयति माहेश्वरी, द्वितीय पुरस्कार दिव्यांशी भूतड़ा तथा तृतीय पुरस्कार जयदीप माहेश्वरी को प्राप्त हुआ। 'संस्कार पोटली प्रतियोगिता' में प्रथम पुरस्कार केशव तथा द्वितीय पुरस्कार पूनम माहेश्वरी को प्रदान किया गया।

सराफा, डीडवाना ओली में सड़क मरम्मत शुरू

ग्वालियर। अमृत योजना के अंतर्गत सराफा बाजार और डीडवाना ओली की मुख्य सड़क की खुदाई कर नई पाइपलाइन डाली गई थी, लेकिन कई महीने गुजरने के बाद सड़क मरम्मत नहीं की गई थी जिससे न सिर्फ इस क्षेत्र के व्यापारी बल्कि आमजन भी परेशान थे।

इसके लिए चेंबर से जुड़े पदाधिकारी और क्षेत्रीय पार्षद संजय सिंहल की पहल पर बुधवार को सड़क मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया। क्षेत्रीय कार्यालय अधिकारी विपिन दुबे ने बताया कि सराफा और डीडवाना ओली में खुदी सड़कों को सीमेंट कंक्रीट से मरम्मत कराया जा रहा है ताकि बारिश में आमजन को परेशान न होना पड़े। वहीं सड़क मरम्मत को चेंबर चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि दो दिन पहले डीडवाना ओली के व्यवसाई माधव अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर यह लिख दिया था कि सड़क नहीं बनी तो वोट नहीं डालेंगे। इसके बाद चेंबर से जुड़े नेता सक्रिय हुए जिससे दबाव के चलते आखिर सड़क मरम्मत कार्य शुरू हो गया। पार्षद संजय सिंहल ने सड़क मरम्मत के दौरान का फोटो भी वायरल किया है। वहीं अध्यक्ष प्रत्याशी पारस जैन ने माधव अग्रवाल की जागरूकता की प्रशंसा की है।

तानसेन नगर में घटिया सीवर निर्माण बना आफत

ऊंचे-नीचे चेंबरों से बढ़ा हादसों और जलभराव का खतरा, रहवासियों का फूटा गुस्सा

नगर संवाददाता ■ ग्वालियर

शहर की पॉश और पुरानी कॉलोनियों में शामिल तानसेन नगर में नई सीवर लाइन का निर्माण अब स्थानीय लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। सीवर समस्या के समाधान के नाम पर की गई यह योजना लापरवाही और घटिया निर्माण कार्य की भेंट चढ़ गई, जिससे पूरा क्षेत्र हादसों और जलभराव के खतरे में आ गया है।

एमआईजी हाउस क्रमांक 424 से 429 तक हाल ही में पार्षद निधि से स्वीकृत सीवर लाइन का कार्य पेटी कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से कराया गया था। लेकिन निर्माण कार्य में गुणवत्ता के मानकों की खुलेआम अनदेखी की गई। आरोप है कि ठेकेदार ने सीवर चैंबरों को सड़क के समतल स्तर पर बनाने की बजाय कहीं ऊंचा तो कहीं नीचे कर दिया, जिससे सड़क पूरी तरह असंतुलित हो गई है।

स्थानीय रहवासियों के अनुसार, क्षेत्र में लगभग 4 से 6 मुख्य चैंबर सड़क से ऊपर-नीचे बने हुए हैं, जो अब दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। आए दिन दोपहिया वाहन चालक इन उभरे हुए चैंबरों से टकराकर गिरकर घायल हो रहे हैं। स्थिति यह है कि सड़क से गुजरना भी लोगों के लिए जोखिम भरा हो गया है। रहवासियों ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य में संबंधित इंजीनियरों और ठेकेदार की घोर लापरवाही के चलते न केवल सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है, बल्कि पहले से बनी मजबूत सड़क को भी पूरी तरह खोदकर बर्बाद कर दिया गया है। अब हालात ऐसे हैं कि सड़क पर गड्ढे और ऊंचे चैंबर मिलकर खतरा और बढ़ा रहे हैं। सबसे गंभीर चिंता यह जताई जा रही है कि असंतुलित चैंबरों और क्षतिग्रस्त सड़क के कारण क्षेत्र में अभी से जलभराव की स्थिति बनने लगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सुधार नहीं किया गया तो आगामी मानसून में तानसेन नगर पूरी तरह जलमग्न हो सकता है और लोगों को घरों से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। इस स्थिति को देखते हुए क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश है। लोगों ने निगमायुक्त से मांग की है कि इस पूरे निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। साथ ही पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे जिम्मेदार ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। रहवासियों ने यह भी मांग की है कि सभी ऊंचे-नीचे चैंबरों को तत्काल सड़क के समतल स्तर पर लाया जाए और क्षतिग्रस्त सड़क की अविलंब मरम्मत कराई जाए, ताकि मानसून से पहले इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान हो सके और क्षेत्रवासियों को राहत मिल सके।

कांग्रेस कार्यालय पर मंडलम् अध्यक्षों का स्वागत

ग्वालियर। कांग्रेस कार्यालय शिंदे की छावनी पर बुधवार को शहर जिला कांग्रेस द्वारा महानगर के सभी नवनियुक्त मंडलम् अध्यक्षों का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने तथा जनता के हितों के लिए संघर्ष तेज करने का संकल्प लिया। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुरेन्द्र यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त किए गए मंडलम् अध्यक्ष संगठन की रीढ़ साबित होंगे। कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य केवल चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि जनता के अधिकारों की रक्षा करना और लोकतंत्र को मजबूत करना है। कार्यक्रम में संगठन महामंत्री इब्राहिम पठान, ब्लॉक अध्यक्ष मुनेन्द्र भदौरिया, अनूप शिवहरे, संदीप यादव, श्याम सुंदर श्रीवास्तव, राजेश तोमर, लक्ष्मी माथुर, रेखा, महेश धनोलिया, अंसार खान, कुलदीप व्यास, हरि जाटव, मनीष शर्मा, डॉ. एनके सिसोदिया, गिर्राज चंदोरिया, उषा शिवहरे आदि उपस्थित रहे।

सड़क निर्माण कार्य का भूमिपूजनः वार्ड क्रमांक 53 में क्षेत्रवासियों की मांग को पूरा करते हुए सड़क निर्माण कार्य का विधिवत भूमिपूजन किया गया। कार्यक्रम में शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुरेन्द्र यादव मौजूद रहे।

मानसून या बारिश की राह में अल नीनो बाधक बन खड़ा हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों के पूर्वानुमान अगर गलत साबित न हुए, तो इस साल कम बरसेंगे बादल। ऐसे में, अनेक सवाल खड़े होने लगे हैं।

कितना कम बरसेंगे बादल

हम कृषि और उपज को कैसे बचाएंगे? जल संकट से कैसे बचेंगे? आने वाले दिनों में हमें सेहत के लिए क्या सावधानियां बरतनी पड़ेंगी? आइए, विशेषज्ञों से जानें कि हमें कैसे सचेत रहना है...

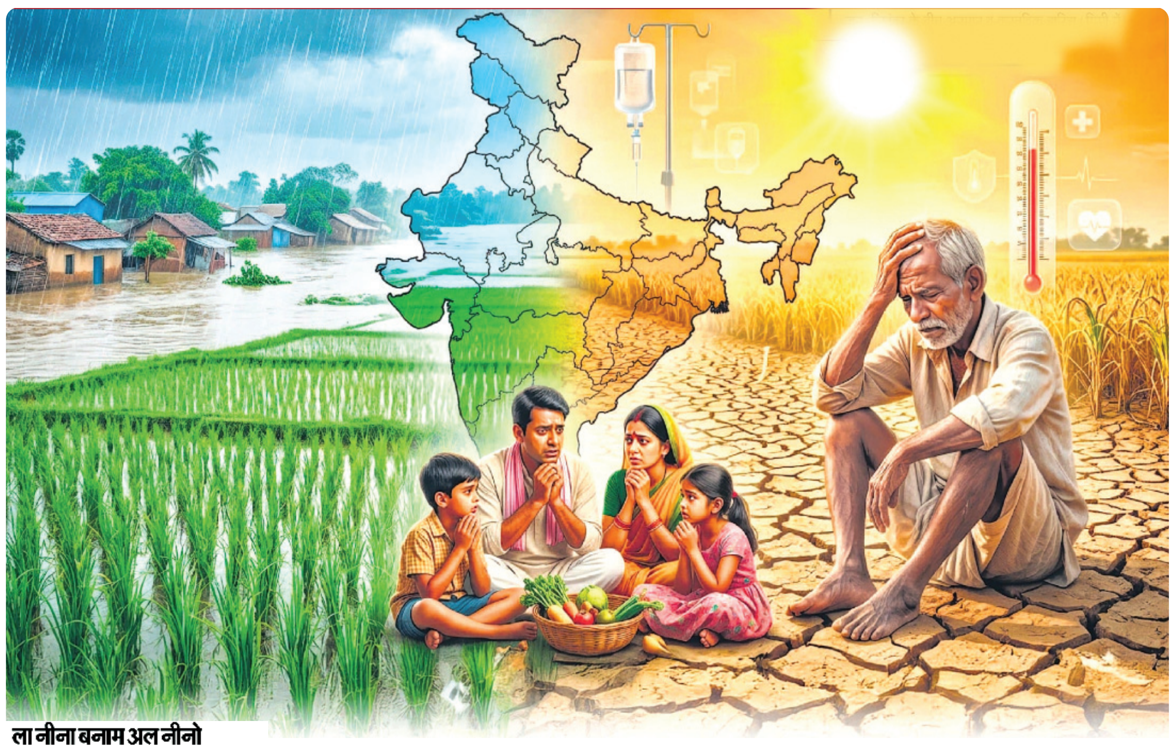

मौसम वैज्ञानिकों ने अल नीनो के आगमन की पुष्टि कर दी है। अगर हालात में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, तो इस बार अपने देश में बारिश कम होगी। अल नीनो वास्तव में भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में होने वाली गर्मी है, जो विश्वभर में मौसम के पैटर्न को प्रभावित करती है। भारत में यह कमजोर मानसून की आशंका को बढ़ाती है। इस वर्ष का अल नीनो दशकों में सबसे मजबूत रहने की आशंका है और यह 2027 की शुरुआत तक जारी रह सकता है।

11 जून को अमेरिका के राष्ट्रीय महासागरीय व वायुमंडलीय प्रशासन (एनओएए) ने भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में अल नीनो के उभरने की घोषणा कर दी। पूर्वानुमान के अनुसार, अल नीनो प्रभाव पूरे वर्ष मजबूत रहेगा। नवंबर-दिसंबर के आसपास चरम पर पहुंचेगा और फरवरी-मार्च 2027 तक जारी रहेगा। अल नीनो की वजह से समुद्र की सतह के तापमान में सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक वृद्धि होने की 63 प्रतिशत संभावना जताई गई है। इस बार अल नीनो को बहुत प्रभावी श्रेणी का माना जा रहा है। साल 1951 के बाद से ऐसी केवल छह या सात घटनाएं देखने में आई हैं।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भी अल नीनो के उभरने की पुष्टि की है और कहा है कि जून-सितंबर में दक्षिण-पश्चिमी मानसून के आगे बढ़ने के साथ इसके और मजबूत होने की आशंका है।

भारत पर क्या होगा प्रभाव?

अल नीनो आमतौर पर प्रशांत महासागर के ऊपर चलने वाली हवाओं को कमजोर करके भारतीय मानसून को दबा देता है। इसके परिणामस्वरूप, भारत की ओर बढ़ने वाली नमी से भरी मानसूनी हवाओं की गति धीमी पड़ जाती है। 1951 से अब तक, 16 अल नीनो वर्षों में से 12 वर्षों में सामान्य से कम या अपर्याप्त वर्षा हुई, जबकि छह या सात वर्ष स्थिति ज्यादा खराब रही। वर्षा को सामान्य से कम तब माना जाता है, जब यह दीर्घकालिक औसत का 90-95 प्रतिशत हो और अपर्याप्त तब माना जाता है, जब यह उस मानक से 10 प्रतिशत से अधिक कम हो। आशंका है कि इस साल 2015 के बाद सबसे कमजोर मानसून रहेगा।

4 जून को केरल तट पर तीन दिन देरी से पहुंचने के बाद, 14 जून तक मानसून में 28.4 प्रतिशत की वर्षा की कमी दर्ज की। यदि अगले महीने भी यह कमी बनी रहती है, तो खरीफ फसलों की बुआई प्रभावित होगी। उपज पर असर पड़ेगा।

तब भी सुधार की कुछ उम्मीद जरूर है। एक सुखद संभावना यह बन सकती है कि हिंद महासागरीय द्विध्रुव (आईओडी) की सकारात्मक स्थिति, जिसमें पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में पश्चिमी हिंद महासागर का पानी अधिक गर्म होता है, मानसून पर अल नीनो के कुछ प्रतिकूल प्रभावों को कम कर सकती है।

खाद्य उत्पादन पर असर

खाद्य उत्पादन पर असर एक बार फिर, बहुत कुछ मानसून की बारिश पर निर्भर करेगा। कुछ इलाकों में ज्यादा बारिश होती है, तो कुछ इलाकों में कम। वैसे, ज्यादा चिंता की बात नहीं है, भारत के पास चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वह मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है। हालांकि, भारत में वार्षिक वर्षा का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा चार महीने के मानसून के मौसम में प्राप्त होता है। इसलिए कमजोर मानसून के परिणाम कृषि से परे भी होंगे। मानसून की बारिश भूजल को रिचार्ज करती है, जलाशयों को भरती है और घरों और उद्योगों के लिए जल आपूर्ति सुनिश्चित करती है। यह जलविद्युत उत्पादन के लिए भी महत्वपूर्ण है।

ला नीना बनाम अल नीनो

अल नीनो हो, तो कम बारिश और ला नीना हो, तो ज्यादा बारिश। आइए जानें साल 1950 से 2025 के बीच हुई वर्षा का हाल।

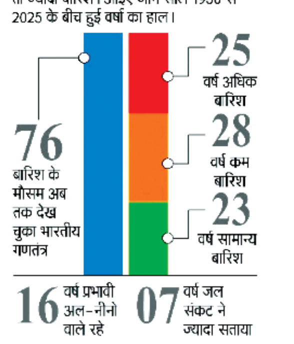

अगले साल तक रहने की आशंका

अल नीनो के सर्दियों में और मजबूत होने और 2027 तक जारी रहने की आशंका के साथ, अगले साल उच्च तापमान का खतरा बना रहेगा। भारत के कुछ हिस्सों में पीने के पानी की कमी हो सकती है।

दस्तकः अनेक आशंकाएं लिए आ पहुंचा

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के नए अल नीनो/ला नीना अपडेट के अनुसार, जून-अगस्त 2026 के दौरान अल नीनो की घटना होने की 80 प्रतिशत आशंका बन गई है। इसके नवंबर तक जारी रहने की आशंका लगभग 90 प्रतिशत या उससे भी अधिक है। हालांकि, अल नीनो की चरम तीव्रता और समय को लेकर कुछ अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन पूर्वानुमान मॉडल बताते हैं कि यह कम से कम मध्यम तीव्रता का होगा।

देशः बचाव की कितनी तैयारी

भारत में खुदरा खाद्य मुद्रास्फीति जनवरी में 2.1 प्रतिशत से बढ़कर मई में 4.8 प्रतिशत हो गई है। वैसे, ईरान में युद्ध थमने से भारत में महंगाई का दबाव घटेगा, लेकिन अल नीनो का दबाव बढ़ेगा। भारत में जल और अन्य जरूरी चीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही सेहत पर भी ज्यादा ध्यान देना होगा। भारत के पास अनाज भंडार पर्याप्त हैं, लेकिन तिलहन और दलहन पर असर पड़ सकता है। सब्जियों के कीमतें बढ़ेंगी।

दुनियाः 50+ देशों पर असर

अल नीनो के प्राथमिक और प्रत्यक्ष प्रभाव विश्वभर के कम से कम 30 से 50 देशों पर पड़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, साल 2015 के अल नीनो में भी ऐसा ही हुआ था और करीब छह करोड़ लोग इससे सीधे प्रभावित हुए थे। दुनिया में कहीं सूखा पड़ेगा, तो कहीं भारी बारिश भी होगी। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका, सोमालिया, दक्षिण सूडान, सूडान सहित कम से कम तीन महाद्वीपों में इसका असर दिखेगा। सजग देश तैयारी में लग गए हैं।

खेती-बागवानी को जरूरत के हिसाब से बदलाना पड़ेगा

विशेषज्ञों के अनुसार भारत की कृषि व्यवस्था पहले से ही जलवायु परिवर्तन की अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे में, वर्ष 2026 के लिए विभिन्न मौसम एजेंसियों और भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी दीर्घकालीन पूर्वानुमान चिंताजनक हैं। अनेक आकलनों के अनुसार, देश में कुल मानसूनी वर्षा दीर्घकालीन औसत का मात्र 90-92 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसके अलावा, वर्षा का असमान वितरण, लंबे शुष्क अंतराल और मानसून की अपेक्षाकृत शीघ्र वापसी के हालात बन सकते हैं।

ऐसे समय में वैज्ञानिक खेती और जलवायु-स्मार्ट कृषि तकनीकों को अपनाना ही जोखिम को कम करने का सबसे प्रभावी उपाय है। 2026 जैसे संभावित सूखा प्रभावित मौसम में किसानों को कम अवधि वाली किस्मों का चयन करना चाहिए।

भारत में ऐसे बीज उपलब्ध हैं, जिनसे कम समय में उपज ली जा सकती है। किसानों को अपने नजदीकी विज्ञान केंद्रों से जरूर संपर्क करना चाहिए। प्रतिकूल मौसम के अनुकूल धान, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, ज्वार, बाजरा की कम अवधि वाली किस्मों का चयन करना चाहिए। ऐसे में, बुवाई में जल्दबाजी करना अक्सर नुकसानदायक साबित होता है। विशेषज्ञों की सर्वसम्मति है कि कम से कम 75-100 मिमी प्रभावी वर्षा होने का इंतजार करें। मिट्टी में पर्याप्त नमी बनने की पुष्टि करें। समय पर बुवाई के अनेक लाभ हैं। इससे बेहतर अंकुरण दर - 85-90 प्रतिशत तक हो जाती है। सिंचाई की आवश्यकता में कमी आती है। करीब 15 से 20 प्रतिशत तक जल बचाया जा सकता है।

तापमान वृद्धि का प्रभाव

पिछले तीन दशक में भारत के औसत तापमान में 0.7 से 1.0 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। यह एक छोटा-सा अंतर लगता है, लेकिन कृषि पर इसके प्रभाव असाधारण हैं। तापमान में वृद्धि के साथ पौधों की जल आवश्यकता भी बढ़ती जाती है। कम वर्षा और अधिक तापमान का संयुक्त प्रभाव मिट्टी की नमी को तेजी से कम करता है। इस स्थिति को नमी तनाव कहा जाता है। जब पौधे नमी तनाव के संपर्क में आते हैं, तब निम्नलिखित प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं-

प्रकाश संश्लेषण में कमी

पत्तियों के रंध्र बंद हो जाने से ऊर्जा का अवशोषण कम होता है।

- पुष्पन में विलंब

पौधों का प्रजनन चक्रबाधित होता है।

- फलन में गिरावट

फूल और फल झड़ने की घटनाएं बढ़ती हैं।

- उपज में नुकसान

कभी-कभी 30-50 प्रतिशत तक नुकसान।

कुछ कृषि तकनीकें अपनाई जा सकती हैं- पिछली फसल के अवशेषों को खेत में ही रहने देने से मिट्टी की सतह पर छाया रहती है और वाष्पीकरण भी 25 से 30 प्रतिशत तक कम होता है। साथ ही, मिट्टी में जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है।

अल नीनो के दौरान सेहत सलामत रखने के लिए रहना होगा बहुत ज्यादा सावधान

चिकित्सक एवं जन स्वास्थ्य विशेषज्ञो के अनुसार अल नीनो का खतरा अगर बढ़ा, तो सबसे पहले पेयजल का अभाव बढ़ेगा। सामान्य तौर पर गर्मी के दिनों में हर किसी तक शुद्ध पेयजल की पहुंच नहीं रहती है, पर अब शुद्ध जल के लिए लोगों को ज्यादा जूझना पड़ेगा।

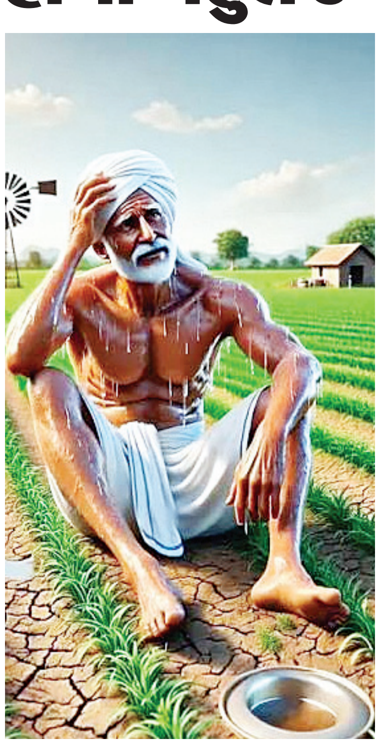

बारिश कम होगी, तो तापमान बढ़ेगा। लू लगने के मामले बढ़ेंगे। अक्सर बच्चे जरूरत से कम पानी पीते हैं और उन्हें लू जल्दी लगती है। थोड़ी भी देर वह खुले में खेलते हैं, तो लू के शिकार हो सकते हैं।

जो लोग धूप में रहकर काम करते हैं, उन्हें खास तौर पर सावधान रहना होगा। मजदूरों से धूप में काम लेने वालों को भी काम के तरीके और समय में बदलाव के लिए सोचना होगा। जो लोग पहले से ही बीमार हैं, उन्हें भी सावधानी बढ़ानी पड़ेगी। ज्यादा तापमान का असर शरीर के सभी अंगों पर पड़ता है। वैसे, अपने देश में यह कोई पहली बार नहीं है, जब बारिश कम होने की आशंका है। फिर भी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सचेत रहना जरूरी है।

जल के अभाव से जीवनशैली खराब हो जाती है। लोग साफ-सफाई में कमी करने लगते हैं। बर्तन के ठीक से साफ न होने, खाद्य सामग्री में स्वच्छता न होने से तरह-तरह के संक्रमणों को बल मिलता है। कुछ संक्रमण थोड़ी भी लापरवाही होने पर जानलेवा हो जाते हैं। कम वर्षा के समय दूषित जल-जनित बीमारियां बढ़ती हैं, जो लंबे समय तक शरीर को बीमार या कमजोर रखती हैं।

जल के अभाव का असर

जल के अभाव में सार्वजनिक रूप से भी गंदगी बढ़ती है, इससे जन स्वास्थ्य प्रभावित होता है। मान लीजिए, आप घर में साफ-सफाई के प्रति पूरी तरह सचेत व आश्वस्त हैं, पर घर से बाहर खतरा बना रहता है। बाहर खाने का चलन भी बढ़ रहा है, लेकिन जल की जब कमी होगी, तब बाहर खाने-पीने की हर चीज की गुणवत्ता प्रभावित होगी। अतः बहुत सोच-समझकर ही बाहर खाना फायदेमंद होगा। यह ठीक से समझ लेना होगा कि अल नीनो का असर हमारी सेहत पर पड़ेगा, लेकिन हम इंतजाम से चलें, तो अपना बचाव कर पाएंगे।

भारत में अल नीनो के प्रभाव और सरकार के राहत व सुधार उपाय

कमजोर मानसून, सूखा और कृषि संकट से निपटने के लिए भारत सरकार की रणनीति और नीतिगत कदम

अल नीनो एक ऐसी जलवायु घटना है जो भारत के मानसून को सीधे प्रभावित करती है। पिछले कई दशकों में लगभग 16 बार अल नीनो की स्थिति बनी है, जिसके कारण देश के कई हिस्सों में वर्षा में कमी, सूखा, और कृषि उत्पादन में गिरावट देखी गई। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने समय के साथ कई योजनाएं और सुधारात्मक कदम उठाए हैं, जिससे लोगों को राहत मिल सकी।

सरकार ने किए प्रमुख उपाय

भारत सरकार ने अल नीनो के प्रभाव को कम करने के लिए बहुस्तरीय रणनीति अपनाई है। इसमें सबसे पहले मौसम पूर्वानुमान प्रणाली को मजबूत किया गया। भारतीय मौसम विभाग द्वारा अब सैटेलाइट और सुपरकंप्यूटर आधारित मॉनिटरिंग से मानसून की बेहतर भविष्यवाणी की जाती है, जिससे किसानों को पहले से जानकारी मिल सके।

जल संरक्षण पर ध्यान

इसके अलावा, जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया, जिससे सूखे क्षेत्रों में भी पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। छोटे और मध्यम किसानों को ड्रिप इरिगेशन और माइक्रो इरिगेशन तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

फसल बीमा को मजबूत

कृषि क्षेत्र में फसल बीमा योजना को मजबूत किया गया, ताकि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके। इसके साथ ही सूखा संभावित क्षेत्रों में वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा दिया गया, जिससे किसानों की आय स्थिर रह सके।

जल भंडारण

ग्रामीण क्षेत्रों में जल भंडारण संरचनाओं जैसे तालाब, चेक डैम और रेनवॉटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दिया गया है। हालांकि अल नीनो व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन सरकार द्वारा किए गए तकनीकी, कृषि और जल प्रबंधन सुधारों से इसके प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा रहा है।

Research

भारत ने 16 वर्ष अल नीनो को झेला, इसमें 7 वर्ष सबसे कठिन रहे

अल नीनो एक प्राकृतिक जलवायु घटना है, जिसमें प्रशांत महासागर का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है। इसका सीधा असर भारत के मानसून पर पड़ता है। जब अल नीनो सक्रिय होता है, तो भारत में वर्षा कम होने और सूखे की स्थिति बनने की संभावना बढ़ जाती है। भारत में पिछले कई दशकों में लगभग 16 बार अल नीनो का प्रभाव देखा गया है, जिनमें 7 वर्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहे हैं।

वर्ष 1982-83 : मजबूत अल नीनो

इस अवधि में मजबूत अल नीनो देखा गया। भारत में मानसून कमजोर रहा और कई क्षेत्रों में सामान्य से कम वर्षा दर्ज हुई। कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ और कुछ राज्यों में सूखे जैसी स्थिति बनी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक असर पड़ा।

वर्ष 1997-98: तापमान बढ़ा

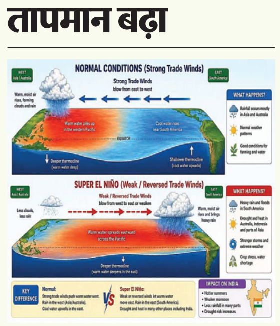

यह एक अत्यंत शक्ति शाली अल नीनो वर्ष था। वैश्विक तापमान असामान्य रूप से बढ़ा। भारत में मानसून में असमानता देखी गई, कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश और कई हिस्सों में सूखा रहा। मौसम पैटर्न पूरी तरह असंतुलित हो गया था।

वर्ष 2002: गंभीर सूखा पड़ा

इस वर्ष भारत में गंभीर सूखा पड़ा। मानसून बहुत कमजोर रहा और कई राज्यों में खेती बुरी तरह प्रभावित हुई। खाद्य उत्पादन में गिरावट आई और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक दबाव बढ़ गया। यह वर्ष अल नीनो के प्रभाव का बड़ा उदाहरण माना जाता है।

वर्ष 2009: मानसून कमजोर रहा

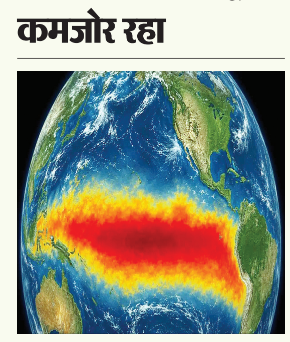

इस वर्ष अल नीनो के कारण मानसून कमजोर रहा। भारत में वर्षा सामान्य से कम हुई। विशेष रूप से मध्य और उत्तर भारत में सूखे जैसी स्थिति बनी। कृषि उत्पादन घटा और महंगाई पर भी असर देखने को मिला।

वर्ष 2015-16: जलसंकट बढ़ा

इस अवधि में मध्यम से मजबूत अल नीनो सक्रिय रहा। भारत में मानसून कमजोर पड़ा और कई राज्यों में वर्षा कम रही। सूखे की स्थिति बनी और जल संकट की समस्या बढ़ी। खेती और जल भंडारण पर इसका बड़ा असर पड़ा।

वर्ष 2018: आंशिक प्रभाव पड़ा

इस वर्ष अल नीनो कमजोर था, लेकिन फिर भी मानसून पर आंशिक प्रभाव पड़ा। कुछ क्षेत्रों में वर्षा कम और कुछ में सामान्य से अधिक बारिश हुई। मौसम में अस्थिरता देखी गई और कृषि पर मिश्रित प्रभाव पड़ा।

वर्ष 2023: कहीं अतिवृष्टि, कहीं कम

यह वर्ष वैश्विक स्तर पर अल नीनो के प्रभाव के कारण चर्चा में रहा। भारत में मानसून में असमानता देखी गई। कुछ राज्यों में भारी बारिश और कुछ में कम वर्षा हुई। तापमान भी सामान्य से अधिक दर्ज किया गया।

निष्कर्ष अल नीनो भारत की जलवायु प्रणाली को सीधे प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण प्राकृतिक घटना है। इसके कारण मानसून में असमानता, कहीं सूखा तो कहीं अत्यधिक बारिश जैसी स्थितियां बनती हैं। इसका सबसे बड़ा प्रभाव कृषि उत्पादन, जल संसाधनों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसलिए अल नीनो की समय पर जानकारी और पूर्वानुमान भारत के लिए अत्यंत आवश्यक है, ताकि नुकसान को कम किया जा सके और बेहतर तैयारी की जा सके।

फीफा विश्व कप 2026 | मैच 55
ग्रुप ई | 26 जून | 01:30 बजे (भारतीय समय)
कुराकाओ बनाम आइवरी कोस्ट
फिलाडेल्फिया स्टेडियम, अमेरिका
81 ◂ फीफा रैंक ▸ 31
कुल आमने-सामने
एक दूसरे के खिलाफ पहले कभी नहीं खेले

फीफा विश्व कप 2026 | मैच 56
ग्रुप ई | 25 जून | 1:30 बजे (भारतीय समय)
इक्वाडोर बनाम जर्मनी
न्यूयॉर्क/न्यू जर्सी स्टेडियम, अमेरिका
30 ◂ फीफा रैंक ▸ 9
कुल आमने-सामने
इक्वाडोर जीता: 0 | जर्मनी जीता: 2

फीफा विश्व कप 2026 | मैच 58
ग्रुप एफ | 26 जून | प्रातः 4:30 बजे (भारतीय समय)
ट्यूनीशिया बनाम नीदरलैंड
कैनसस सिटी स्टेडियम, अमेरिका
57 ◂ फीफा रैंक ▸ 8
कुल आमने-सामने
ट्यूनीशिया जीता: 0 | नीदरलैंड जीता: 1 | ड्रॉ: 2

फुटबॉल वर्ल्ड कप में क्रोएशिया ने पनामा को हराया नॉकआउट की उम्मीदें कायम, पनामा बाहर

एजेंसी, टोरंटो

एंटे बुदिमिर के गोल के दम पर क्रोएशिया ने फुटबॉल वर्ल्ड कप में बुधवार को पनामा को 1-0 से हराया। इस जीत के साथ क्रोएशिया ने नॉकआउट दौर में पहुंचने की अपनी उम्मीदें बरकरार रखीं हैं। जबकि पनामा टूर्नामेंट से बाहर हो गया। टोरंटो स्टेडियम में ग्रुप-एल के इस मैच के पहले हाफ में दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। हालांकि, कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। पनामा की डिफेंस लाइन ने क्रोएशिया के हमलों को अच्छी तरह रोके रखा। फिर दूसरे हाफ में क्रोएशिया के एंटे बुदिमिर मैदान पर उतरने के चार मिनट बाद ही गोल करने में सफल रहे। उन्होंने 54वें मिनट में जोसिप स्तानिशिच के सटीक क्रॉस पर आसान गोल दागा। इस गोल ने क्रोएशिया को 1-0 की बढ़त दिला दी। जोकि आखिरी तक कायम रही।

गोलकीपर लिवाकोविच ने 3 अटैक रोके: मैच के 67वें मिनट में पनामा ने बराबरी के लिए लगातार तीन प्रयास किए, लेकिन गोलकीपर डोमिनिक लिवाकोविच ने शानदार बचाव करते हुए सभी मौके विफल कर दिए।

मोड्रिच ने 200वां इंटरनेशनल मैच खेला

40 साल के लुका मोड्रिच ने करियर का 200वां इंटरनेशनल मैच खेला। उन्होंने 57वें मिनट में मार्को पालिच के लिए शानदार मौका बनाया, लेकिन पनामा के गोलकीपर ऑरलैंडो मॉस्केरा ने बेहतरीन बचाव किया।

रोनाल्डो लगातार 6 वर्ल्डकप में गोल करने वाले पहले फुटबॉलर

एजेंसी, ह्यूस्टन

पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो लगातार 6 फुटबॉल वर्ल्डकप में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने मंगलवार रात को उज्बेकिस्तान के खिलाफ छठे मिनट में गोल करके यह उपलब्धि हासिल की। 41 साल के रोनाल्डो 2006, 2010, 2014, 2018 और 2022 के वर्ल्ड कप में भी गोल स्कोर कर चुके हैं। उन्होंने अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ा। मेसी ने 2006, 2014, 2018, 2022 और 2026 वर्ल्ड कप में गोल किए हैं। लेकिन, वे 2010 के एडिशन में गोल नहीं कर सके। ह्यूस्टन स्टेडियम में खेले गए इस मैच में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। रोनाल्डो ने अपना पहला वर्ल्डकप गोल 2006 में 21 साल की उम्र में किया था। उनके नाम सबसे ज्यादा 145 इंटरनेशनल गोल हैं। रोनाल्डो 230वां इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे।

पुर्तगाल के लिए सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड भी बनाया

रोनाल्डो ने मैच में 2 गोल दागे पुर्तगाल के टॉप स्कोरर

रोनाल्डो ने 39वें मिनट में अपना दूसरा गोल दागा। इसी के साथ वे पुर्तगाल के लिए वर्ल्डकप में सबसे ज्यादा 10 गोल करने वाले प्लेयर भी बन गए। उन्होंने यूसेबियो के 9 गोल के रिकार्ड को पीछे छोड़ा। मैच में रोनाल्डो के अलावा, नूनो मेंडेस (17वें मिनट) और राफेल लेओ (87वें मिनट) ने गोल किया। 59वें मिनट में उज्बेकिस्तान के गोलकीपर अब्दुवोहिद नेमातोव से बॉल टकराकर गोल में चली गई। इसे ओन गोल माना गया। मौजूदा टूर्नामेंट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 गोल हो चुके हैं। वे पहले मैच में डीआर कांगो के खिलाफ गोल नहीं कर सके थे।

क्रॉस पर मौका चूके रोनाल्डो 2 मिनट बाद गोल

मैच की शुरुआत से ही पुर्तगाल अटैकिंग दिखा। चौथे मिनट में नूनो मेंडेस के क्रॉस पर रोनाल्डो मौका चूक गए, लेकिन दो मिनट बाद उन्होंने गलती नहीं दोहराई। जोआओ कैंसिलो के लो क्रॉस पर रोनाल्डो ने शानदार राइट-फुटेड शॉट लगाकर गेंद को नेट में पहुंचाया। इसी गोल के साथ वह 6 वर्ल्डकप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए।

घाना के गोलकीपर असारे का कमाल; इंग्लैंड के 19 अटैक रोके

एजेंसी, बूस्टन

बूस्टन स्टेडियम में ग्रुप-एल के एक अन्य मैच में इंग्लैंड और घाना ने गोलरहित ड्रॉ खेला गया। इंग्लैंड ने पूरे मैच में 19 शॉट लगाए, जबकि घाना सिर्फ एक शॉट ही लगा सका। घाना ने अहम एक अंक हासिल कर लिया। 86वें मिनट में निको ओ'राइली का हेडर क्रॉसबार से टकराया। हैरी केन के पास रिबाउंड पर गोल करने का मौका था, लेकिन उनका प्रयास लक्ष्य से ऊपर निकल गया। घाना के लिए सबसे अच्छा अवसर 78वें मिनट में बना, जब अब्दुल फतावू ने शानदार रन लगाकर प्रिंस अडू को पास दिया। हालांकि इंग्लैंड के डिफेंडर एजरी कोन्सा ने समय रहते हस्तक्षेप कर खतरा टाल दिया। घाना ने इस मौके पर पेनल्टी की मांग की, लेकिन रेफरी ने इसे नकार दिया। घाना के कोच कार्लोस क्वेइरोज ने मैच के बाद कहा कि उनकी टीम की योजना इंग्लैंड को शुरुआत से ही रोकने और निराश करने की थी, जिसमें वे सफल रहे।

इंग्लैंड टॉप पर आया, पनामा बाहर: ग्रुप एल में अब इंग्लैंड और घाना 4-4 अंकों के साथ टॉप-2 पर हैं, जबकि क्रोएशिया के 3 अंक हैं। आखिरी ग्रुप मैच में क्रोएशिया का मैच घाना से होगा। पनामा की टीम लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप में बिना कोई अंक हासिल किए बाहर हो गई।

फीफा विश्व कप 2026 | मैच 60
ग्रुप डी | 26 जून | प्रातः 7:30 बजे (भारतीय समय)
पैराग्वे बनाम ऑस्ट्रेलिया
सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम, अमेरिका
37 ◂ फीफा रैंक ▸ 26
कुल आमने-सामने
पैराग्वे जीता: 0 | ऑस्ट्रेलिया जीता: 2 | ड्रॉ: 3

फीफा विश्व कप 2026 | मैच 57
ग्रुप एफ | 26 जून | प्रातः 4:30 बजे (भारतीय समय)
जापान बनाम स्वीडन
डलास स्टेडियम, अमेरिका
16 ◂ फीफा रैंक ▸ 36
कुल आमने-सामने
जापान जीता: 1 | स्वीडन जीता: 2 | ड्रॉ: 2

फीफा विश्व कप 2026 | मैच 59
ग्रुप डी | 26 जून | प्रातः 7:30 बजे (भारतीय समय)
तुर्किये बनाम अमेरिका
लॉस एंजिल्स स्टेडियम, अमेरिका
32 ◂ फीफा रैंक ▸ 14
कुल आमने-सामने
तुर्किये जीता: 2 | अमेरिका जीता: 2 | ड्रॉ: 1

आईसीसी रैंकिंग- शुभमन गिल नंबर-2 वनडे बल्लेबाज, ईशान किशन की 21 स्थान की छलांग

एजेंसी, दुबई

अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में टॉप स्कोरर रहे भारतीय कप्तान शुभमन गिल की आईसीसी रैंकिंग में उछाल आया है। वह वनडे में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। इससे पहले वह पांचवें नंबर पर थे। बुधवार को जारी हुई साप्ताहिक रैंकिंग में गिल वनडे नंबर-1 पर काबिज न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल से सिर्फ 24 रेटिंग अंक पीछे हैं। गिल ने अफगानिस्तान के खिलाफ हालिया तीन मैचों की वनडे सीरीज में 238 रन बनाए थे। वहीं, ईशान किशन 21 स्थान की लंबी छलांग लगाकर 43वें नंबर पर पहुंच गए हैं। भारतीय बॉलर प्रसिद्ध कृष्णा को 34 और अर्शदीप सिंह को 16 स्थान का फायदा मिला है। टेस्ट रैंकिंग में न्यूजीलैंड के मैट हैनरी भारत के जसप्रीत बुमराह के साथ संयुक्त रूप से नंबर-1 गेंदबाज बन गए हैं। यह 36 साल बाद है, जब न्यूजीलैंड का कोई गेंदबाज पहले स्थान पर आया है। इससे पहले 1990 में रिचर्ड हैडली टेस्ट के टॉप गेंदबाज थे।

रोहित चौथे नंबर पर बरकरार, विराट को एक पायदान का नुकसान

विराट कोहली हैमस्ट्रिंग चोट के कारण अफगानिस्तान के खिलाफ खेली गई सीरीज से बाहर हो गए थे। विराट की रैंकिंग पर इसका असर पड़ा है। पिछले हफ्ते वह दूसरी पोजिशन पर थे, इस बार खिसक कर तीसरे नंबर पर आ गए हैं। जबकि रोहित शर्मा चौथे स्थान पर बने हुए हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में उन्होंने 143 रन बनाए थे, जिसमें एक फिफ्टी शामिल है।

तीन भारतीय गेंदबाजों को भी फायदा

वनडे में गेंदबाजों की रैंकिंग में भारत के तीन खिलाड़ियों ने बड़ी छलांग लगाई है। अर्शदीप सिंह 16 स्थान ऊपर चढ़कर 22वें नंबर पर पहुंच गए हैं। प्रसिद्ध कृष्णा 34 पायदान की बढ़त के साथ 58वें स्थान पर आ गए हैं, जबकि वॉशिंगटन सुंदर 17 स्थान की छलांग लगाकर संयुक्त रूप से 71वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में अफगानिस्तान के राशिद खान पहले, पाकिस्तान के अबरार अहमद दूसरे और इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर तीसरे स्थान पर हैं।

जैकॉब ने 110 मीटर हर्डल 12.75 सेकंड में पूरी की

रेस से पहले चीजबर्गर खाने वाले 20 वर्षीय अमेरिकी एथलीट ने बनाया विश्व रिकॉर्ड

एजेंसी, न्यूयॉर्क

क्या कोई एथलीट अपनी सबसे अहम रेस से ठीक पहले भारी-भरकम फास्ट फूड खाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता है? 20 साल के अमेरिकी एथलीट जैकॉब थार्प ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। ऑबर्न यूनिवर्सिटी के इस युवा छात्र ने 110 मीटर स्प्रिंट हर्डल को महज 12.75 सेकंड में पूरा कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। अपनी शानदार जीत के साथ-साथ जैकॉब अपने अनोखे प्री-रेस रूटीन के लिए भी चर्चा में हैं। रेस से पहले उनका फिक्स मील है: दो चीजबर्गर, लार्ज फ्रेंच फ्राइज और चिकन नगेट्स। यूजीन (ओरेगन) में आयोजित NCAA चैम्पियनशिप में जैकॉब ने यह ऐतिहासिक कारनामा किया। उन्होंने 2012 में बेल्जियम में एरीस मेरिट द्वारा बनाए गए पुराने रिकॉर्ड को 0.05 सेकंड से पीछे छोड़ दिया। इस टूर्नामेंट में आने से पहले

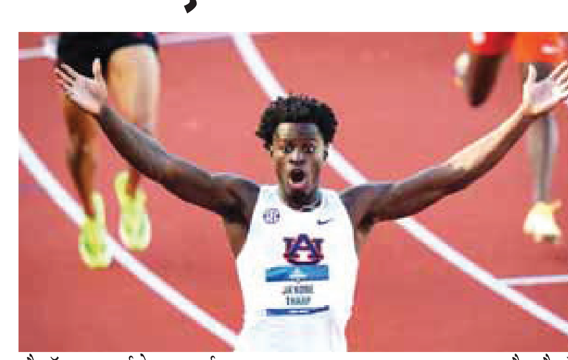

जैकॉब का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 13.01 सेकंड था। अपने समय में 0.26 सेकंड का सुधार लाकर उन्होंने दुनिया को चौंका दिया है। जैकॉब अब दुनिया भर में मशहूर हो चुके हैं, लेकिन उनका असली लक्ष्य अभी बाकी है। उनकी नजर अब 2027 के बीजिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप और 2028 के लॉस एंजिलिस ओलिंपिक पर है। जैकॉब अपनी रिकॉर्ड-ब्रेकिंग रेस का वीडियो 15 बार देख चुके हैं ताकि यह समझ सकें कि और कहां समय बचाया जा सकता है। जैकॉब का मानना है कि रेस की आखिरी 3 बाधाओं पर सबसे ज्यादा फोकस की जरूरत होती है। वे कहते हैं, 'जब आप इतनी तेज दौड़ रहे होते हैं, तो बाधाएं बहुत जल्दी सामने आती हैं और आपका शरीर धीमा होना चाहता है। लेकिन आपको एक 'कामिकेज पायलट' की तरह खतरे की ओर बिना डरे हमला करते रहना होता है।' जैकॉब के माता-पिता बास्केटबॉल खिलाड़ी रहे हैं। शुरुआत में जैकॉब भी बास्केटबॉल और ट्रैक दोनों में हाथ आजमाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने सिर्फ दौड़ने को अपना करियर चुना।

बतौर अंधविश्वास शुरू किया था फास्ट फूड खाना

जैकॉब अपनी हर बड़ी रेस से पहले मैकडॉनल्ड्स का फास्ट फूड खाते हैं। यह कोई शौक नहीं, बल्कि उनका एक अंधविश्वास (सुपरस्टिशन) बन चुका है। हाई स्कूल के दौरान स्टेट चैम्पियनशिप में उन्होंने यही मील खाया था और जीत हासिल की थी। तब से हर बड़े इवेंट से पहले वे इसी डाइट को फॉलो कर रहे हैं। उनके कोच केन हार्नडेन (जिम्बाब्वे के दो बार के ओलिम्पियन) को शुरुआत में यह बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन जैकॉब कहते हैं, 'अगर कोई चीज काम कर रही है, तो उसे बदलने की क्या जरूरत है। जब आप किसी चीज से जीतते हैं, तो उसी पर टिके रहना बेहतर है।'

वैभव सूर्यवंशी के छोटे भाई ने दोबारा शतक जमाया

10 साल के आशीर्वाद ने 119 गेंद पर 168 रन बनाए; इसमें 19 चौके, 6 छक्के शामिल

एजेंसी, समस्तीपुर

15 साल के वैभव सूर्यवंशी के छोटे भाई आशीर्वाद ने फिर तूफानी पारी खेली। उन्होंने एक लोकल टूर्नामेंट में 119 गेंद पर 168 रन बनाए। उनकी पारी में 19 चौके और 6 छक्के शामिल रहे। 10 साल के आशीर्वाद ने बुधवार को इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए अपनी पारी की जानकारी दी। उनकी पारी के दम पर ऋषभ-11 ने समस्तीपुर में खेले गए लोकल मैच में वैशाली-11 को हराया। इसी महीने आशीर्वाद ने समस्तीपुर में खेले गए एक स्थानीय प्रैक्टिस मैच में ताजपुर क्रिकेट अकादमी की ओर से खेलते हुए 87 गेंदों पर 103 रन बनाए थे।

पिता ने कहा था- आशीर्वाद को बेहतरीन क्रिकेटर बनाना चाहते हैं: पिता संजीव कह चुके हैं कि वे आशीर्वाद को भी अगले दो साल में वैभव की तरह बेहतरीन क्रिकेटर बनाना चाहते हैं। आशीर्वाद सूर्यवंशी बिहार में क्रिकेट की ट्रेनिंग ले रहे हैं। आशीर्वाद के पिछले शतक के बाद पिता संजीव सूर्यवंशी ने भी सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर की थी। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में लिखा था, मेरे छोटे बेटे आशीर्वाद सूर्यवंशी ने आज प्रैक्टिस मैच में अपना पहला शतक बनाया। आप सभी से अनुरोध है कि आशीर्वाद पर भी अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें।

योजना | विंध्य की खेल प्रतिभाओं को मिलेगा नया मुकाम

रीवा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बनेगा सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक

खेल संवाददाता, भोपाल

मध्यप्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार करने के लिए विश्वस्तरीय खेल अधोसंरचना का विकास समय की आवश्यकता है। उन्होंने रीवा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक के निर्माण के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने बुधवार को मंत्रालय भोपाल में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रीवा के विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने और युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। विंध्य क्षेत्र में आधुनिक खेल सुविधाओं के विकास से खिलाड़ियों को उच्चस्तरीय प्रशिक्षण, अभ्यास और प्रतियोगिताओं के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध होगा। इससे क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा तथा वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकेंगे। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने खेल अधोसंरचना विकास के कार्यों में तेजी लाने तथा खिलाड़ियों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रीवा में सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण क्षेत्र में एथलेटिक्स गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। बैठक में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव संजीव कुमार सिंह उपस्थित थे।

वैभव सूर्यवंशी के लिए इंग्लैंड में अलग चेंजिंग रूम होगा

टीम मीटिंग और खेल के दौरान ही सीनियर्स साथ रहेंगे आईसीसी नियमों के तहत फैसला

एजेंसी, दुबई

15 साल के वैभव सूर्यवंशी इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे पर टीम के बाकी खिलाड़ियों से अलग चेंजिंग रूम इस्तेमाल करेंगे। सूर्यवंशी के लिए यह फैसला आईसीसी और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की अंडर-16 खिलाड़ियों से जुड़ी सेफगार्डिंग पॉलिसी के तहत लिया गया है। हालांकि सूर्यवंशी मैचों के दौरान भारतीय प्लेयर्स के साथ रह सकेंगे और टीम मीटिंग्स का भी हिस्सा होंगे। उन्हें कपड़े बदलने के लिए अलग चेंजिंग रूम और वॉशरूम का इस्तेमाल करना होगा। आईसीसी ने यह नियम 2019 में लागू किया था। इसके बाद एक जुलाई से भारतीय टीम इंग्लैंड में 5 टी-20 और 3 वनडे मैच खेलेगी।

फुटबॉलर मैक्स को अलग चेंजिंग रूम मिला था: इंग्लिश क्लब आर्सेनल के फुटबॉलर मैक्स डोमैन को दिसंबर 2025 में टीम के अन्य खिलाड़ियों से अलग चेंजिंग रूम का इस्तेमाल करना पड़ता था। उस वक्त उनकी उम्र 15 साल थी। खेलों में चाइल्ड सेफगार्डिंग नियम अचानक नहीं बने। सालों तक खेल अकादमियों, ड्रेसिंग रूम और ट्रेनिंग सेंटरों में नाबालिग खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण, मानसिक प्रताड़ना के कई मामले सामने आए।

निर्माण कार्य शुरू करने से पहले श्रम विभाग को सूचना देना अनिवार्य, पोर्टल पर करना होगा पंजीयन

भोपाल। श्रम विभाग द्वारा निर्माण स्थलों पर श्रमिकों की सुरक्षा, स्वस्थ कार्य परिवेश सुनिश्चित करने और उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत अब सभी निर्माण स्थलों पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षा अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। इसके लिए श्रम सेवा पोर्टल मोबाइल ऐप के माध्यम से निर्माण स्थल का विवरण, कर्मचारियों की संख्या भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी भवन या निर्माण कार्य को प्रारंभ करने से कम से कम 30 दिन पहले संबंधित क्षेत्र के अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक को इसकी सूचना देना वैधानिक रूप से अनिवार्य है।

स्थानांतरण प्रक्रिया में पात्र शिक्षकों के लिए पोर्टल की खामी बनी मुसीबत

भोपाल (नगर संवाददाता)

शिक्षा विभाग की स्थानांतरण प्रक्रिया में बड़ी गंभीर विसंगति सामने आई है। इंटरमीडिएट परीक्षा में गणित, विज्ञान अथवा कृषि विषय से उत्तीर्ण ऐसे शिक्षक, जो नियमों के अनुसार प्राथमिक शिक्षक विज्ञान (वर्ग-3 लैब) पद के लिए पात्र हैं। इन्हें एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर स्थानांतरण आवेदन के दौरान उक्त पद का विकल्प उपलब्ध नहीं हो रहा है। जबकि स्कूलों में पद बड़े पैमाने पर खाली है। बुधवार की रात्रि 12:00 बजे के बाद पोर्टल बंद हो जाएगा। विसंगति देखें कि इनके आवेदनों पर प्रभारी मंत्री भी अनुशंसा कर चुके, लेकिन पोर्टल पर पद प्रदर्शित नहीं होने के कारण दिक्कत बढ़ गई है। आरोप है कि इस खामी से पात्र शिक्षक अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार, विभाग में वर्षों से अनेक शिक्षक विज्ञान (वर्ग-3 लैब) पद पर पदस्थापना और स्थानांतरण की पात्रता रखते हैं। इसके बावजूद पोर्टल पर संबंधित विकल्प प्रदर्शित न होने के कारण वे अपनी योग्यता एवं पात्रता के अनुरूप आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि यह स्थिति स्थानांतरण नीति की भावना के विपरीत है और इससे पात्र अभ्यर्थियों को अनावश्यक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

बड़ी संख्या में प्रक्रिया से बाहर होंगे टीचर: प्रभावित शिक्षकों का कहना है कि यदि पोर्टल पर विज्ञान (वर्ग-3 लैब) का विकल्प उपलब्ध नहीं कराया गया तो बड़ी संख्या में शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। इससे न केवल शिक्षकों के हित प्रभावित होंगे, बल्कि स्थानांतरण प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर भी प्रश्न खड़े होंगे। एजुकेशन पोर्टल 3.0 में तकनीकी त्रुटि से प्राथमिक शिक्षक विज्ञान (वर्ग-3 लैब) का विकल्प न खुलने के कारण सवा लाख टीचर प्रभावित हो रहे हैं।

शिक्षक संघों ने लिखा मंत्री एवं डीपीआई को पत्र: इस मामले में शिक्षक संघों ने विभाग के मंत्री एवं लोक शिक्षण संचालनालय को पत्र लिखा है। विभागीय अधिकारियों से शीघ्र हस्तक्षेप कर समस्या का समाधान करने तथा स्थानांतरण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के भेदभाव या विसंगति को दूर करने की अपील की है।

शिक्षकों के स्वैच्छिक ट्रांसफर के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की अनिवार्यता हटी, लेकिन तकनीकी समस्या बरकरार

भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्वैच्छिक तबादलों में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जमा करने की अनिवार्यता हटा दी है। अब पति-पत्नी के आधार पर तबादले के लिए आवेदन करने वाले शिक्षक मैरिज सर्टिफिकेट के बजाय समग्र आईडी, सत्यापित सेवा पुस्तिका (सर्विस बुक) की प्रति या अन्य दस्तावेज जमा कर सकेंगे। लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। इससे उन शिक्षकों को राहत मिलेगी, जिनके पास विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र नहीं है और वे आवेदन नहीं कर पा रहे थे। दरअसल, 6 जून को जारी तबादला नीति में विवाह प्रमाण पत्र की अनिवार्यता का जिक्र नहीं था, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पर मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड करना जरूरी बताया जा रहा था। इस कारण बड़ी संख्या में शिक्षक-शिक्षिकाएं परेशान थे। मुद्दा सामने आने के बाद विभाग ने स्पष्टीकरण जारी कर नियम स्पष्ट कर दिया।

ऑनलाइन आवेदन को लेकर अब भी परेशानी : मैरिज सर्टिफिकेट से जुड़ी समस्या दूर होने के बावजूद स्वैच्छिक तबादला प्रक्रिया में कई तकनीकी और नीतिगत दिक्कतें बनी हुई हैं। आवेदन की अंतिम तिथि होने के बावजूद कई शिक्षक आवेदन पूरा नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षक संगठनों के अनुसार 90 प्रतिशत ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता, जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों पर तबादला प्रतिबंध और तीन वर्ष की सेवा अवधि जैसी शर्तों के कारण बड़ी संख्या में शिक्षक पहले ही प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं। वहीं दिव्यांग और गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षकों को भी पोर्टल की तकनीकी खामियों का सामना करना पड़ रहा है। दिव्यांग शिक्षकों से एक वर्ष के भीतर जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, जबकि अधिकांश के पास स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र हैं। पोर्टल इन्हें स्वीकार नहीं कर रहा है।

हमीदिया में फायर सिस्टम बंद, 10 हाईराइज बिल्डिंगों व कोचिंगों में एक ही एंट्री और एग्जिट

फायर डिपार्टमेंट ने सर्वे कर ओरस, राठी और दुर्रानी समेत 40 को थमाया नोटिस

लखनऊ हादसे के बाद जांच तेज, कई कोचिंग फायर सेफ्टी में फेल

भोपाल (नगर संवाददाता)

नगर निगम के फायर डिपार्टमेंट ने राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल के साथ ही 10 हाई राइज बिल्डिंग और ओरस, राठी और दुर्रानी समेत 40 कोचिंग संस्थानों को नोटिस थमाए हैं।

यह नोटिस फायर सिस्टम बंद मिलने और वेंटीलेशन के साथ ही आने-जाने का एक ही रास्ता होने पर मिले हैं। हाल ही में निगम के फायर डिपार्टमेंट ने इनका सर्वे किया था। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक शहर में अभी भी कई बहुमंजिला इमारतों में फायर सेफ्टी का पालन नहीं किया जा रहा है। जिस कारण अगजनी के समय बड़ी दुर्घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है। दरअसल दो दिन पहले लखनऊ की एक कोचिंग में हुई अगजनी की घटना के बाद भोपाल के एमपी नगर, पिपलानी, न्यू मार्केट टीटी और बैरागढ़ में संचालित कोचिंग संस्थानों की जांच की गई।

ननि के फायर ऑफिसर सौरभ पटेल के मुताबिक फायर कंट्रोल समय-समय पर मॉल, हाई-राइज बिल्डिंग, होटल, सिनेमा हॉल और सरकारी-प्राईवेट हॉस्पिटल, कोचिंग संस्थानों की जांच करता है। इस जांच में देखा जाता है कि फायर सिस्टम काम कर रहे हैं या नहीं? इसके अलावा अगजनी की घटना के समय अंदर मौजूद लोग आसानी से बाहर निकल सकते हैं या नहीं? यह सब देखा जाता है। फायर सेफ्टी रूल्स के मुताबिक 15 मीटर के भवन के लिए फायर एनओसी लेना अनिवार्य है।

अस्पताल में आगजनी का बनेगा खतरा

हाल ही में नगर निगम के फायर डिपार्टमेंट ने राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल का सर्वे किया था। जहां अस्पताल के सिर्फ दो ब्लॉकों में ही फायर सिस्टम काम करते मिले। यानि अस्पताल में कोई अगजनी की घटना हुई तो मरीजों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसको देखते हुए निगम ने अस्पताल प्रबंधक को नोटिस जारी किया है।

10 बहुमंजिला इमारतों में भी सेफ्टी जीरो

फायर ऑफिसर सौरभ पटेल ने बताया कि हाई-राइज बिल्डिंग कान्हा टॉवर शहर के अलग-अलग इलाकों में मौजूद 10 बहुमंजिला इमारतों में फायर सेफ्टी का पालन न होने पर नोटिस जारी किए गए हैं। पटेल के मुताबिक 15 मीटर ऊंचाई वाली बिल्डिंग के लिए फायर एनओसी जरूरी है। फिर भी शहर में ज्यादातर बिल्डिंगों के पास फायर एनओसी नहीं है। इसमें तुलसी टॉवर का भी नाम शामिल है। तुलसी टॉवर की एनओसी को पहले ही कैंसिल किया जा चुका है।

80 से अधिक कोचिंगों में किया था सर्वे

लखनऊ कोचिंग सेंटर हादसे के बाद नगर निगम के फायर डिपार्टमेंट ने भोपाल की लगभग 80 से अधिक कोचिंग संस्थानों का सर्वे किया था। इनमें से 39 को बुधवार को नोटिस जारी किए गए हैं। कोचिंग सेंटरों में फायर सिस्टम बंद मिले, कहीं वेंटीलेशन नहीं था। इसके अलावा कोचिंग सेंटरों में स्टूडेंट आने और जाने में एक ही रास्ते का उपयोग कर रह थे। जो फायर सेफ्टी रूल्स के विपरित है। बताया जाता है कि भोपाल में करीब 300 कोचिंग इंस्टिट्यूट हैं। जिसमें से 200 कोचिंग एमपी नगर में ही मौजूद है। जबकि अलग-अलग इलाकों में 100 छोटे सेंटर संचालित हैं। जिसमें लभग ढाई लाख स्टूडेंट्स पढ़ते हैं।

इनका कहना है

फायर डिपार्टमेंट का लगातार सर्वे हो रहा है और संबंधितों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अभी तक 40 नोटिस देने की कार्रवाई की गई है। वहीं टीमें जांच भी कर रही हैं।

■ **सौरभ पटेल,** फायर ऑफिसर

सीएसआर से एम्स को मिलीं 6.2 करोड़ की मशीनें, हृदय यूरोलॉजी इलाज होगा मजबूत

भोपाल (नगर संवाददाता)

प्रदेश और आसपास के राज्यों के मरीजों को बेहतर एवं अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एम्स भोपाल को बड़ी सौगात मिली है।

एचडीएफसी बैंक की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पहल परिवर्तनद्य के तहत गैर-सरकारी संगठन डॉक्टर्स फॉर यू (डीएफवाई) के सहयोग से संस्थान को लगभग 6.2 करोड़ रुपए मूल्य की अत्याधुनिक चिकित्सा मशीनें प्रदान की गई हैं।

एम्स भोपाल को प्राप्त उपकरणों में कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी (सीटीवीएस) विभाग के लिए एडवांस्ड हार्ट-लंग मशीन, सीटीवीएस आईसीयू के लिए अत्याधुनिक कार्डियक मॉनिटर्स, मल्टीपल प्रोब्स से युक्त हाई-एंड इकोकार्डियोग्राफी मशीन व इनहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड मशीन शामिल हैं। वहीं यूरोलॉजी विभाग को 3-डी विज़न सपोर्ट से लैस 4के एडवांस्ड एंडोविजन सिस्टम भी उपलब्ध कराया है। विशेषज्ञों के अनुसार नई हार्ट-लंग मशीन व अन्य उपकरणों के जरिए सीटीवीएस विभाग अधिक संख्या में जटिल हृदय शल्य चिकित्सा करने में सक्षम होगा। साथ ही हृदय व फेफड़ा प्रत्यारोपण जैसी उन्नत सेवाओं को भी नई मजबूती मिलेगी। वहीं 4 च एंडोविजन सिस्टम की मदद से यूरोलॉजी विभाग में जटिल सर्जरी अधिक सटीकता और बेहतर परिणामों के साथ की जा सकेंगी।

एम्स भोपाल की ओर से कार्यपालक निदेशक एवं सीईओ प्रो. (डॉ.) माधवानन्द कर, उपनिदेशक (प्रशासन) संदेश जैन, चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विकास गुप्ता तथा अधिष्ठाता (अनुसंधान) डॉ. रेहाल उल हक समेत कई वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे। सीटीवीएस विभागाध्यक्ष डॉ. योगेश निवारिया, यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. देवाशीष कौशल, सीएसआर समिति सदस्य डॉ. भूपेश्वरी पटेल, डॉ. विक्रम वट्टी तथा सीएसआर नोडल अधिकारी डॉ. केतन मेहरा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रो. (डॉ.) माधवानन्द कर ने कहा कि अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों से संस्थान की तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं की क्षमता में वृद्धि होगी।

उन्होंने एचडीएफसी बैंक व डॉक्टर्स फॉर यू का आभार व्यक्त करते कहा यह सहयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों को सशक्त बनाने की एक सराहनीय पहल है।

कॉमर्शियल एक्टिविटी पर अरेरा और रोहित नगर के 60 लोगों को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले नगर निगम की तैयारी

भोपाल (नगर संवाददाता)

नगर निगम की बिल्डिंग परमिशन शाखा ने अरेरा कॉलोनी समेत रोहित नगर के 60 मकान मालिकों को नोटिस जारी किए हैं। यह नोटिस रहवासी इलाके में कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए जारी किए हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अनाधिकृत निर्माण सहित लैंड यूज चेंज और स्वीकृत उपयोग के विपरित भवनों में गतिविधियों को लेकर राज्यों से कार्रवाई की जानकारी मांगी थी। इस मामले की 4 अगस्त को सुनवाई होना है। इससे पहले निगम ने यह नोटिस जारी किए हैं।

दरअसल अरेरा कॉलोनी सहित रोहित नगर और शहर के दूसरे रहवासी इलाकों में कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही हैं। मसलन बंगले तोड़कर बड़े शौरूम, अस्पताल, नर्सिंग होम, बैंक, होटल और प्राईवेट कंपनियों के ऑफिस हैं। हालांकि चार साल पहले नगर निगम अरेरा कालोनी और रोहित नगर का सर्वे किया था। तब 83 और 67 से अधिक ऐसे भवन मिले। जहां परमिशन रहवासी की थी, लेकिन मौके पर अस्पताल, नर्सिंग होम, बैंक, होटल, शोरूम संचालित हो रही थीं।

नए सिरे से हो रहा है सर्वे

नगर निगम की बिल्डिंग परमिशन शाखा ने मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 और नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत अरेरा कॉलोनी और रोहित नगर के रहवासियों को नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में बिल्डिंग परमिशन सहित भवन की उपयोगिता, प्रॉपर्टी और वॉटर टैक्स व कनेक्शन की जानकारी मांगी है। अभी तक 60 नोटिस जारी हो चुके हैं। वहीं इलाके में टीमें लगातार सर्वे भी कर रही हैं।

449 महिला व 123 पुरुष आरक्षक लेंगे साइबर ट्रेनिंग

भोपाल। पुलिस उप महानिरीक्षक (ग्रामीण) भोपाल राजेश सिंह चंदेल ने बुधवार को पुलिस प्रशिक्षण शाला भौंरी, में 5वें बैच के 572 नव आरक्षकों के बुनियादी प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ किया। इस बैच में 449 महिला एवं 123 पुरुष नव आरक्षक शामिल हैं, जो पुलिस बल में महिलाओं की बढ़ती सहभागिता और सशक्त उपस्थिति को भी रेखांकित करता है। पुलिस अकादमी के मार्गदर्शन में संचालित यह प्रशिक्षण सत्र नव आरक्षकों को शारीरिक दक्षता, विधिक ज्ञान, पुलिसिंग कौशल, तकनीकी समझ, नेतृत्व क्षमता और जनसेवा के मूलभूत मूल्यों से परिचित कराएगा। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें बदलते अपराध परिदृश्य, साइबर अपराध, महिला एवं बाल सुरक्षा, सामुदायिक पुलिसिंग और नागरिक-केंद्रित पुलिसिंग के विभिन्न आयामों का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम में उपनिदेशक मध्यप्रदेश अकादमी, भोपाल डॉ. संजय कुमार अग्रवाल, सहायक निदेशक प्रशिक्षण रश्मि पाण्डेय सहित वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।

572 नव आरक्षकों के बुनियादी प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ

बारिश में कचरा पृथक्कीकरण और सड़कों से पशुओं को हटाने के निर्देश

भोपाल (नगर संवाददाता)

महापौर मालती राय ने स्वच्छता एवं गोवर्धन परियोजना के कार्यों की समीक्षा की

राजधानी में बुधवार को महापौर मालती राय ने वर्षा ऋतु में स्वच्छता बनाये रखने व पशुओं एवं नागरिकों की सुरक्षा के दृष्टिगत सड़कों से पशुओं को हटाने की कार्यवाही और अधिक तत्परतापूर्वक सुनिश्चित कराने एसबीएम के तहत कई कार्यों एवं गोवर्धन परियोजना शाखा के कार्यों की समीक्षा की।

महापौर ने कचरा पृथक्कीकरण, एकत्रीकरण एवं निष्पादन की कार्यवाही और अधिक बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने, वर्षा ऋतु में आवश्यकतानुसार कीटनाशक रसायनों का छिड़काव करने तथा पशुओं को सड़कों से तत्परतापूर्वक हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान महापौर परिषद के सदस्य, आरके सिंह बघेल, उपायुक्त, हीरेंद्र सिंह कुशवाह समेत निगम के अन्य अधिकारी मौजूद थे।

महापौर राय ने बुधवार को निगम मुख्यालय अटल भवन के सभाकक्ष में एसबीएम के तहत रोड स्वीपिंग, गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन, गोवर्धन परियोजना के तहत स्वतंत्र विचरण करने वाले पशुओं को पकड़कर कांजी हाउस भेजने संबंधी कार्यों आदि की समीक्षा की। समीक्षा कर कहा कि सड़कों पर और अधिक बेहतर ढंग से रोड स्वीपिंग मशीनों का संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

भोपाल के सुनियोजित विकास के लिए जनप्रतिनिधियों ने राज्य वित्त आयोग को दिए सुझाव

स्थानीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाना सर्वोच्च प्राथमिकता : पवैया

भोपाल (नगर संवाददाता)

मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर, सशक्त और सक्षम बनाना आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। स्थानीय निकायों की आर्थिक मजबूती ही नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और समग्र विकास की आधारशिला बनेगी। यह बात राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया ने राजधानी के लालघाटी स्थित विशिष्ट अतिथि गृह में भोपाल के जनप्रतिनिधियों के साथ बुधवार को हुई बैठक में कही।

मास्टर प्लान जल्द लागू करने पर बनी सहमति

राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष श्री पवैया ने सभी जनप्रतिनिधियों से स्थानीय निकायों के स्वयं के राजस्व स्रोत बढ़ाने, वित्तीय स्वावलंबन सुनिश्चित करने तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए व्यवहारिक एवं दीर्घकालिक सुझाव आमंत्रित किए। उन्होंने पर्यटन स्थलों के संरक्षण एवं विकास के लिए विशेष वित्तीय प्रावधानों और संसाधनों के प्रभावी उपयोग पर भी सुझाव मांगे।

राज्य वित्त आयोग की इस बैठक में नगरीय निकायों एवं पंचायतों के वित्तीय सुदृढ़ीकरण, स्वयं के राजस्व स्रोतों में वृद्धि, आधारभूत संरचना विकास तथा जनसुविधाओं के विस्तार से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 के आय-व्यय, स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति और भविष्य की विकास आवश्यकताओं पर विचार-विमर्श हुआ। बैठक में भोपाल के प्रभारी मंत्री चैतन्य काश्यप, सांसद आलोक शर्मा, विधायक भगवानदास सबनानी आदि मौजूद रहे।

निकायों को मिले मुद्रांक शुल्क पर उपकर का लाभ:कश्यप

भोपाल के प्रभारी मंत्री चैतन्य काश्यप ने नगरीय निकायों की वित्तीय स्वायत्तता को मजबूत बनाने के लिए मुद्रांक शुल्क पर अधिरोपित उपकर का लाभ सीधे नगरीय निकायों को दिए जाने तथा शासकीय भवनों द्वारा भी नियमानुसार संपत्ति कर भुगतान सुनिश्चित करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय निकायों के राजस्व में वृद्धि होगी और वे विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कर सकेंगे।

संभागायुक्त ने किया संभागीय कार्यालय का निरीक्षण

भोपाल (नगर संवाददाता)

संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने बुधवार को संभागीय कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया और विभिन्न कार्यालयों में कार्य की प्रगति, दस्तावेजों के संधारण तथा राजस्व प्रकरणों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कर्मचारियों से कार्यप्रणाली, फाइल प्रबंधन और ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की।

शर्मा ने आयुक्त कार्यालय में प्रशासनिक व्यवस्था एवं अनुशासन के लिए विभिन्न अनुभागों स्थापना, लेखा एवं राजस्व में साफ-सफाई एवं फाइलों की उचित रख-रखाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी अधिकारी और कर्मचारी के लिये बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रणाली प्रारंभ करने के निर्देश दिए। अपर आयुक्त राजस्व कार्यालय में रिकार्ड संधारण में शुद्धता और सुव्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए, ताकि किसी भी विभागीय कार्य में अनावश्यक विलंब न हो।

स्वामी, मुद्रण, प्रकाशक एवं संपादक **आशीष दुबे** द्वारा सांई प्रिंटर्स, म. नं. 91, शाप नं. 3, जिन्सी पुलिस चौकी के पास जहांगीराबाद, भोपाल से मुद्रित एवं टी-2, बालाजी टावर, मधुवन बिहार कालोनी मिसरोद भोपाल से प्रकाशित। समस्त विवादों का न्यायालय भोपाल रहेगा।